mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-284 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
13 अक्टूबर 2026 मंगलवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

केरलम मिनी कूपर हादसे के बाद बोला ड्राइवर-पापा संभाल लेंगे

3 स्टूडेंट्स की मौत; बर्थडे पर मिली थी लग्जरी कार, 200किमी. की स्पीड से चलाता था

कोच्चि,एजेंसी। केरलम के कोच्चि में तेज रफ्तार मिनी कूपर कार की टक्कर से तीन लोगों की मौत मामले में ड्राइवर का बयान सामने आया है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद जब उन्होंने आरोपी कार चालक सुहैल सजीव को रोका तो उसने कहा कि उसके पिता सब संभाल लेंगे। कोच्चि के नेदुम्बस्सेरी इलाके में रविवार रात मिनी कूपर कार ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटर सवार तीन छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 साल के इयास, देविका और गोपिका के रूप में हुई है। पुलिस ने सुहैल को गिरफ्तार किया है और उसके तीन साथियों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक, सुहैल शराब के नशे में था। ये लग्जरी कार उसकी मां ने जन्मदिन पर दी थी। उसके 200kmph से ज्यादा की रफ्तार से कार चलाने के वीडियो भी सामने आए हैं। सुहैल और उसके तीनों दोस्त

नशे में थे पुलिस के अनुसार, हादसे के वक्त कार में सुहैल के अलावा निनव, अमीर और जोएल भी मौजूद थे। सुहैल और निनव ने एर्नाकुलम के एक बार में शराब पी थी। बाद में अमीर और जोएल भी उनके साथ शामिल हो गए। दोनों एयरपोर्ट पर अपने दोस्त को लेने पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट में देरी होने के कारण वे सुहैल के साथ मिनी कूपर में तेज रफ्तार से घूमने निकल गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार में सवार दो लोग मौके से भाग गए थे। उन्हें स्थानीय पुलिस की मदद से अलप्पुझा से हिरासत में लिया गया। मामले में सुहैल मुख्य आरोपी है, जबकि निनव, अमीर और जोएल पर अपराध में मदद करने का आरोप है।

तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग... चश्मदीद सलीम ने बताया कि हादसे के समय वे घटनास्थल के पास खड़े थे। अचानक तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद आसपास मौजूद लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने सड़क पर तीन लोगों को घायल हालत में पड़ा देखा। कुछ देर बाद पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

: ब्रीफ बॉक्स :

महाराष्ट्र पीएससी पेपर लीक की जांच के लिए कमेटी बनी

तुकाराम मुंढे सेक्रेटरी नियुक्त; चेयरमैन छुट्टी पर गए, 10 दिन बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म

पुणे,एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (MPSC) में सुधार के लिए रविवार को एक कमेटी बनाई। इसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके बाद कैंडिडेट्स ने 10 दिन से चल रहा प्रदर्शन खत्म कर दिया। राज्य के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को कमेटी बनाने की जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज दिलीप भोसले होंगे। इसमें आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी शामिल होंगे। दरअसल, छत्रपति संभाजीनगर में 30 जून को MPSC की परीक्षाएं कंप्यूटर पर कराने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया था।

मणिपुर में व्यक्ति का कटा सिर लौटाने की मांग

सरकार को नगा संगठन का 48 घंटे का अल्टीमेटम,

गुवाहाटी,एजेंसी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 52 साल के अजिनबोउ आर की हत्या के बाद उनका कटा सिर लौटाने की मांग उठी है। नगा संगठन जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर ने केंद्र और राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने कहा है कि सिर मिलने तक पोस्टमॉर्टम नहीं होने दिया जाएगा। अजिनबोउ की शनिवार को मकुई अशांग गांव में उग्रवादी हमले में हत्या हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हथियारबंद लोगों के बीच उनका कटा सिर दिखा था। बिना सिर वाला शव रविवार रात इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया। मणिपुर में नगा-कुकी हिंसा में शुक्रवार और शनिवार को 10 लोगों की मौत हुई। तनाव के चलते कांगपोकपी और कामजोंग जिलों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया।

होर्मुज के पास जहाज पर ड्रोन हमला, 2 भारतीय लापता

तेहरान,एजेंसी। होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर रविवार को ड्रोन से हमला हुआ। जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से 9 को बचा लिया गया, जबकि 2 अब भी लापता हैं। हमले के पीछे कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर हमले हुए हैं। इनमें से एक हमला रविवार को ही एमटी वाल्थेरा पर हुआ था जबकि दूसरा हमला 9 अक्टूबर को एमटी जेम नंबर 2 पर हुआ। भारत ने जहाजों पर होने वाले हमले तुरंत रोकने को कहा है।

जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार ने रोक लगाई

● सीजेपी ने यहीं 36 दिन धरना दिया था ● धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी। इसकी सिफारिश के आधार पर दिल्ली का रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड प्रदर्शन स्थल बनाए गए हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR पर रोक की मांग को लेकर सोमवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी। पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। इससे पहले CJP ने 20 जून से 25 जुलाई तक NEET पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन किया था। 36 दिन तक चले इस प्रदर्शन के दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। 25 जुलाई को प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म हो गया था। रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड में धरना-प्रदर्शन आयोजित करने की प्रक्रिया और नियमों को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी। फिलहाल आदेश में इन दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

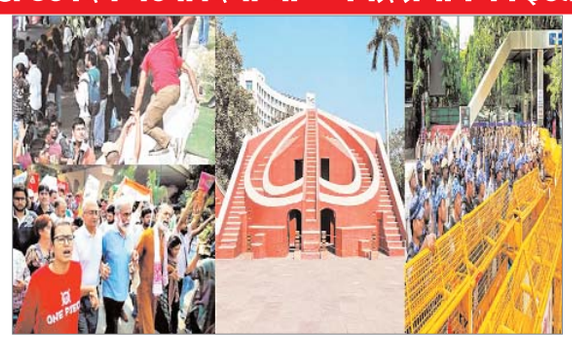

गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी... गृह मंत्रालय ने विरोध-प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई थी। समिति की सिफारिशों के बाद इन तीनों स्थानों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है।

सीजेपी का दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

कहा- प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली तो फिर आंदोलन करेंगे; दीपके बोले- हिरासत का अधूरा वीडियो दिखाया

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख नहीं मिली तो फिर आंदोलन करेंगे। CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास सोमवार को प्रदर्शन की अनुमति मांगने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसी बीच, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत का वीडियो एडिट करके जारी किया है। उन्होंने कहा- हिम्मत है तो पूरा वीडियो दिखाओ। दीपके के मुताबिक, दादी की मौत की खबर सुनने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई से बात करने देने की अपील की। दो मिनट के लिए फोन देने के लिए भी कहा लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। दीपके, रांका और दास को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। वे जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे। रविवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त भी रखी। आशुतोष रांका बोले- पुलिस को लेटर देकर प्रदर्शन की इजाजत मांगी सीजेपी लीडर आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस को लेटर देकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। उन्होंने पुलिस को प्रदर्शन की तारीख तय करने का ऑप्शन भी दिया है।

बिहार एसआईआर पर सुनवाई

फॉर्म-6 पर हमने कोई फैसला नहीं दिया: सुप्रीम कोर्ट

● *न हमारे सामने आया, न मंजूर किया ना ही नामंजूर किया*

पटना,एजेंसी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान इस्तेमाल हुए नए फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उसने नए फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक फैसला नहीं दिया है। इससे फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच बिहार SIR से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने की बात कही है।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा, 'नए फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक फैसला नहीं हुआ है। बिहार SIR मामले की सुनवाई के समय नए फॉर्म-6 का मुद्दा अदालत के सामने था ही नहीं।' इससे पहले 5 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि उसने SIR में इस्तेमाल हो रहे फॉर्म-6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। जस्टिस बागची ने कहा कि नए फॉर्म 6 पर कोई फैसला नहीं हुआ है। CJI ने यह कहा था कि जब बिहार स्ढ्ढक्र मामले में फैसला सुनाया गया था, तब नया फॉर्म 6 मौजूद नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है या मंजूरी नहीं दी है।

शब्दों को चुन-चुन कर इस्तेमाल न करें... सीजेआई जस्टिस बागची ने कहा कि नए फॉर्म 6 पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंजूरी मिली है या नहीं, जब बिहार पर फैसला हुआ था, तब नया फॉर्म 6 कोर्ट के सामने नहीं था। वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कृपया न्यूज आइटम के लिए शब्दों को चुन-चुनकर इस्तेमाल न करें।

सीजेआई बोले- विपक्ष को नहीं मिल पाने की वजह बताई

सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले; राहुल की मुलाकात की मांग ठुकराई थी, कहा- याचिका लगाएं

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि उन्होंने INDIA ब्लॉक के सांसदों को मुलाकात नहीं कर पाने की वजह बता दी है। उन्होंने कहा कि रविवार को विपक्ष का पत्र मिला था, जिसका जवाब उन्होंने उसी रात दे दिया था। जवाब में उन्होंने मुलाकात नहीं कर पाने के कारण बताए हैं। CJI ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि को याचिका दायर करने का अधिकार है। कोर्ट उनकी समस्याएं सुनेगा और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेगा। दरअसल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने CJI से सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच मिलने का समय मांगा था।

समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों का काल बनेगा स्वदेशी युद्धपोत 'मंगरोल'

भारतीय नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल

मुंबई,एजेंसी। भारतीय नौसेना ने सोमवार को मुंबई में अपने तीसरे एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट मंगरोल को बेड़े में शामिल (कमिशन) कर लिया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित यह स्वदेशी युद्धपोत उथले और तटीय पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने में सक्षम है।

80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित इस पोत के शामिल होने से नौसेना की बंदरगाहों और तटीय इलाकों की सुरक्षा करने और बड़े बेड़े के अभियानों में मदद करने की क्षमता बढ़ेगी। समुद्री सुरक्षा के बदलते परिदृश्य और पानी के नीचे बढ़ते खतरों के बीच, 'मंगरोल' का बेड़े में शामिल होना भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर तटीय और उथले समुद्री इलाकों में। मुंबई में आयोजित इस कमिशनिंग समारोह की अध्यक्षता वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की।

तेलंगाना सीएम बोले- कांग्रेस राम और भाजपा रावण

पणजी,एजेंसी। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने गोवा में कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए रामायण का उदाहरण देकर कांग्रेस और भाजपा की तुलना की। उन्होंने कहा कि भाजपा रावण है, जो लोगों को बांट रही है, जबकि कांग्रेस राम है। अगर आप रावण को हराना चाहते हैं, तो आपको राम का समर्थन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी।

योगी बोले: कांग्रेस को नेतृत्व बदलाना चाहिए:सपा को किसानों का श्राप ले डूबा

गोरखपुर में 9.18 लाख किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

गोरखपुर,एजेंसी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए अराजकता फैलाने से बाज नहीं आई तो जनता उसका बचा-खुचा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त कर देगी। योगी ने कहा कि कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। जिस नेतृत्व पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है, उसे बदलने की आवश्यकता है। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हुदहुद तूफान आया तो केंद्र ने किसानों की मदद के लिए 3,200 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन 800 करोड़ रुपए बांटकर बाकी रकम हड़प ली गई। किसानों का श्राप लगा और सपा सरकार चली गई। सीएम गोरखपुर में सोमवार को किसानों को राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां से उन्होंने प्रदेश के 9.18 लाख किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की। यह रकम बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई।

इससे पहले मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 500 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। योगी बोले- कांग्रेसी और समाजवादी लोग पैसा डकार जाते थे सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय केंद्र से 100 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन नीचे तक पहुंचते-पहुंचते 15 रुपए रह जाते थे।

देश में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिजली सप्लाई होगी

आईआईटी बॉम्बे ने बनाया, केरलम में शुरुआत; इससे बिजली बिल में 30% की कमी आई

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV से यात्रा करने के साथ उसकी बैटरी का इस्तेमाल घर में बिजली सप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं। बॉम्बे की ग्रिड इंटीग्रेशन लैब ने IIT कैंपस में तीन साल तक प्रयोग किए। इस दौरान दिन में इलेक्ट्रिक कार सोलर पैनल से चार्ज होती और रात में एक प्रोफेसर के घर में बिजली सप्लाई करती। इसने घर के सभी उपकरणों का लोड उठाया और प्रोफेसर के बिजली बिल में करीब 30% की कमी भी आई। EV की बैटरी से घर में बिजली सप्लाई करने को व्हीकल टू होम और वापस ग्रिड को बिजली भेजने को व्हीकल टू ग्रिड कहते हैं। IIT बॉम्बे ने देश में पहली बार यह प्रोजेक्ट बनाया। अब केरलम में इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। केरलम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ जुलाई 2025 में एमओयू साइन किया। इसके तहत 100 से ज्यादा EV को वी2जी तकनीक से जोड़कर उनकी बैटरी की बिजली घरों में इस्तेमाल की जाएगी। इससे केरलम में बिजली की समस्या भी दूर होगी। प्रो. जाकिर बोले- EV से घर में बिजली देने पर बैटरी लाइफ पर असर नहीं पड़ा IIT बॉम्बे ग्रिड इंटीग्रेशन लैब के प्रों जाकिर हुसैन राथर ने कहा कि EV से घर की लाइट लगातार सप्लाई के बाद भी बैटरी लाइफ पर खास फर्क नहीं पड़ा। बैटरी लाइफ को एसओएच से मापते हैं।

सऊदी अरब पर 10 साल में सबसे बड़ा हमला

हूती विद्रोहियों ने रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, भारतीय समेत 13 लोगों की मौत

रियाद/नई दिल्ली,एजेंसी। यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार रात सऊदी अरब में रियाद एयरपोर्ट पर हमला किया। इसमें एक भारतीय समेत 13 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद सऊदी सरकार ने रियाद एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन रोक दिया। हालांकि अगले ही दिन रविवार को हूती विद्रोहियों ने घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्मिनल पर हमला कर दिया। इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुआ हमला पिछले एक दशक में सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले मई 2015 में एक सऊदी के कातिफ में एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ था जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी।

इंटरनेशनल उड़ानें बंद, अब घरेलू ऊड़ान पर भी संकट ... हूती विद्रोहियों के हमले के बाद रियाद एयरपोर्ट की इंटरनेशनल उड़ानें शनिवार से ही बंद हैं। विद्रोहियों ने एयरपोर्ट और सऊदी के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व बीजेपी विधायक अतर सिंह भड़ाना की लाठी-पत्थर से पीट-पीटकर हत्या

70 से 80 लोगों ने किया हमला, क्रेशर को लेकर चल रहा था विवाद

भरतपुर, एजेंसी। राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अतर सिंह भड़ाना की कथित हमले में मौत हो गई। घटना भौंड़ा गांव में हुई, जहां क्रेशर खनन लीज को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों के मुताबिक, रविवार शाम प्लांट पर पहुंचे अतर सिंह पर 70 से 80 लोगों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में उनके सहयोगी गगन शर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अतर सिंह भड़ाना की पत्नी कमलेश के अनुसार, वह रविवार शाम करीब 6:30 बजे भौंड़ा गांव स्थित अपने क्रेशर खनन लीज प्लांट पर पहुंचे थे। इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमले में अतर सिंह और उनके सहयोगी गगन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।दोनों घायलों को तत्काल वैर अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर अतर सिंह को जयपुर और गगन शर्मा को भरतपुर रेफर किया गया। अतर सिंह भड़ाना को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्स्स् थानाधिकारी जितेंद्र कुमार के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे उपचार के दौरान पूर्व विधायक की मौत हो गई। वहीं, घायल गगन शर्मा का भरतपुर में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद भौंड़ा गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर के मुताबिक, घटना के बाद गांव में पुरुषों की मौजूदगी नहीं होने की बात भी सामने आई है। विवाद से जुड़े दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतर सिंह भड़ाना मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने वर्ष 2003 में राजस्थान की वैर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक का पद संभाला था। उनकी मौत की खबर के बाद इलाके में घटना को लेकर चर्चा है।

मुंबई की अदिति ने सबसे तेज 100 मीटर स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की 12 साल की अदिति मांजरेकर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है और 100 मीटर स्केटिंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. अदिति ने 'इनलाइन स्केट्स बैकवर्ड कैटेगरी' में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया और यह कारनामा सिर्फ 17.96 सेकंड में पूरा किया. पूर्वी मुंबई के उपनगर भांडुप में रहने वाले अदिति के पिता प्रसाद मांजरेकर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में उसकी सफलता का श्रेय उसकी कड़ी मेहनत और निरंतरता को दिया. वहीं अदिति ने कहा कि वह अपने माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल कर पाई हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह मेरे माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हो पाया है. मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूं. भविष्य में, मैं देश के लिए खेलना चाहती हूं.' प्रसाद मांजरेकर ने कहा कि उनकी बेटी ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत की और कड़ी ट्रेनिंग ली. उसकी इस कामयाबी से उसके घर में खुशी का माहौल है. प्रसाद ने कहा, 'हम भविष्य में भी अदिति को स्केटिंग में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे. मैं चाहता हूं कि वह भारत का प्रतिनिधित्व करे.' अदिति बहुत साधारण परिवार से हैं और उनके पिता एक कैफे चलाते हैं. उन्होंने अपने कैफे के सामने ही एक स्केटिंग कोच से ट्रेनिंग ली. शुरू में उसके माता-पिता को लगा कि वह हार मान लेगी, उन्हें यह नहीं पता था कि वह लगातार डटी रहेगी और एक रिकॉर्ड बनाएगी. अदिति ने प्रतिदिन दो से ढाई घंटे अभ्यास किया और पिछले तीन वर्षों में 26 पदक जीते. अदिति ने उस खास सूची में जगह बनाने के लिए कर्नाटक के बेलगाम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की. प्रसाद ने कहा, 'उस समय हममें से कोई भी उसके साथ नहीं था. रिकॉर्ड बनाने में उसने जो दृढ़ निश्चय दिखाया, उस पर हमें सचमुच गर्व है।

चोरी हुई कार का क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के हक में सुनाया फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई कुछ दिनों की देरी को आधार बनाकर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार चोरी के एक मामले में पीड़ित कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह बात कही। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से क्लेम इस तरह खारिज करने को सेवा में गंभीर लापरवाही माना है। आयोग के अध्यक्ष सुखवीर सिंह मल्होत्रा और सदस्य रवि कुमार की बेंच ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित को कार का बीमा मूल्य (आईडीवी) का 75 प्रतिशत यानी 4.31 लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। इसके अलावा, मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 12,500 रुपये का भुगतान

करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि 30 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बीमा कंपनी को 12त्न सालाना दर से ब्याज देना होगा। आयोग ने कहा कि नियमों में उलझाकर बीमा कंपनी पीड़ित को उसके हक से वंचित नहीं कर सकती।

पीड़ित युवक की शिकायत पर चार दिन बाद दर्ज हुआ केस

यह मामला शकरपुर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की मारुति एस-क्रॉस कार 26 दिसंबर 2019 को गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित सेक्टर-12 से चोरी हो गई थी। उन्होंने उसी दिन विजय नगर थाने में इसकी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया। वीरेंद्र ने कार का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसके लिए उन्होंने प्रीमियम भी दिया था। बीमा पॉलिसी 27 फरवरी 2019 से 26 फरवरी 2020 तक वैध थी। कार का घोषित बीमा मूल्य करीब 5.75 लाख रुपये था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने बीमा कंपनी को 2 जनवरी 2020 को चोरी की सूचना दी, लेकिन बीमा कंपनी ने देरी का हवाला देकर उनका क्लेम खारिज कर दिया।

दलीलों को खारिज किया

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि चोरी की सूचना पुलिस को देर से दी गई और कंपनी को भी समय पर जानकारी नहीं मिली। ऐसे में पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण क्लेम खारिज करना उचित था। आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने आदेश में कहा कि इसे आधार बनाकर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता।

कभी नारी सुरक्षा के सवालों से घिरा यूपी अब बना सामर्थ्य की नई पहचान : सीएम योगी

लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से इसके महत्व पर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी के तप और संकल्प से सिद्धि का मंत्र हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी सिद्ध किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 2017 से पहले और इसके बाद के उत्तर प्रदेश की तुलना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा रहने वाला उत्तर प्रदेश आज नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना है। विगत 9.5 वर्षों में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, तकनीक आधारित निगरानी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियानों ने प्रदेश में महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई है।

सीएम योगी ने आगे कहा कि मिशन शक्ति के पांच चरणों, सेफ सिटी परियोजना, मिशन शक्ति केंद्रों और महिला बीट पुलिसिंग जैसी पहलों ने महिला सुरक्षा तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्यबल में महिलाओं के योगदान का भी जिक्र किया और कहा कि 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश महिला पुलिस कार्यबल 10,000 से बढ़कर 44,000 से अधिक हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर 3 महिला पीएसी बटालियनों का भी गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की नारी सुरक्षा से सशक्तीकरण की यह अहर्निश यात्रा 'सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार कर रही है। इससे पहले सीएम योगी ने अपनी पाती में शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अहंकार, दुराग्रह, आसक्ति और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विनम्रता, साहस, शक्ति, संकल्प, न्याय और धर्म की विजय का भाव मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में निहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति को सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाना इसी चेतना का आधार है। उन्होंने प्रदेशवासियों से नवरात्र पर महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा और महिला स्वावलंबन के लिए योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की।

बारिश के बाद बढ़े मच्छरों के प्रकोप से राहत के लिए नगरपालिका ने कराई फॉगिंग

बयाना। बारिश के मौसम के बाद शहर में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को कम करने और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से नगरपालिका की ओर से सोमवार को शहर के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग कराई गई। नगरपालिका के इस कदम से स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिली। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक पवन कुमार सैन ने बताया कि बारिश के बाद मच्छरों की संख्या बढ़ने से मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में फॉगिंग कराई गई है, ताकि मच्छरों के प्रकोप को कम किया जा सके और आमजन को राहत मिल सके। सोमवार को नगरपालिका की ओर से दमदमा रोड, मीराना रोड, सुभाष चौक, बजरिया सहित शहर के विभिन्न वार्डों और बाजारों में फॉगिंग कराई गई। इस दौरान प्रमुख मार्गों और आबादी वाले क्षेत्रों में मच्छरों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। नगरपालिका क्षेत्र के लोगों ने बताया कि नगरपालिका की ओर से कराई गई फॉगिंग से मच्छरों के प्रकोप में कमी आने की उम्मीद है। इससे आमजन को राहत मिलेगी और मच्छर जनित बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद मिलेगी। नगरपालिका की ओर से कराए गए इस कार्य की स्थानीय लोगों ने सराहना की। लोगों का कहना है

कि बारिश के बाद मच्छरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जानी चाहिए, ताकि शहरवासियों को मच्छरों से राहत मिल सके।

अद्भुत कलाकृति: छात्र ने सूखी लाल मिर्च से बनाई दुर्गा की मूर्ति

सोनारपुर , एजेंसी। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में इस साल पूजा पंडाल आने वाले श्रद्धलुओं को देवी दुर्गा अलग रूप में दिखेंगी. दरअसल, 21 साल के जयमाल्या मंडल ने सिर्फ सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा मूर्ति बनाई है. जयमाल्या मंडल अभी सोनारपुर कॉलेज में स्नातक के छात्र हैं. उनके लिए आर्ट सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि अपनी कल्पना को सच करने का एक माध्यम है. बचपन से ही उन्हें अलग-अलग वस्तुओं से नई चीजें बनाने में गहरी दिलचस्पी रही है. उन्होंने पहले भी मिट्टी से दुर्गा की मूर्तियां बनाई हैं. इस साल, उन्हें कुछ अलग करने की इच्छा हुई. इसी सोच ने उन्हें एक नया माध्यम खोजने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके घर के आसपास मिलने वाली अलग-अलग चीजों के साथ अनुभव करना शामिल था. आखिरकार, उन्होंने दुर्गा मूर्ति के लिए रसोई की सूखी लाल मिर्च को चुना. यह पहली बार नहीं है जब जयमाल्या मंडल ने स्थानीय लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से हैरान किया है; उन्होंने पहले भी तेजपत्ते और माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके देवी की मूर्तियां बनाई हैं. ऐसी कोशिशों से, यह युवा आर्टिस्ट सोनारपुर के लोगों को अपनी कला दिखाने की कोशिश करता है. अनोखे माध्यमों से दुर्गा

की मूर्तियां बनाना उनका जुनून है. कई दिनों की मेहनत के बाद, उन्होंने सूखी लाल मिर्च से दुर्गा की मूर्ति बनाने में सफलता हासिल की. महालया के दिन 'चक्षु दान' (मूर्ति की आंखें बनाने की रस्म) पूरा हुआ. अब, यह अद्भुत कलाकृति एक स्थानीय पूजा पंडाल में दर्शन के लिए रखी जाएगी. आर्टिस्ट ने पिछले साल 'इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया था. जयमाल्या मंडल कहते हैं, 'मैंने 2022 में मिट्टी की दुर्गा मूर्ति, 2023 में माचिस की तीली से दुर्गा मूर्ति और 2024 में तेजपत्ते से दुर्गा मूर्ति बनाई थी. पिछले साल - 2025 में - मैंने बेल के पत्तों से दुर्गा मूर्ति बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. हर साल दुर्गा पूजा के दौरान, मुझे मूर्ति बनाने के नए-नए विचार आते हैं. इस साल, मैंने सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा मूर्ति बनाई. बहुत अच्छा लग रहा है. '

परिवार का मिला समर्थन: जयमाल्या का परिवार भी इस अनोखी पहल के लिए प्रोत्साहन का एक स्रोत रहा है. उनके माता-पिता और बहन ने बचपन से ही उनके रचनात्मक प्रयासों का समर्थन किया है. उनके पिता रंजीत मंडल–जो पेशे से एक शिक्षक हैं–कहते हैं, 'मेरे बेटे को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है. वह सिर्फ अपनी दिलचस्पी, कल्पना और प्रयास से एक के बाद एक नई रचनाएं तैयार करता आ रहा है. ' वहीं, उनकी बहन भूमिका मंडल कहती हैं, 'जैसे ही दुर्गा पूजा पास आती है, मेरा भाई कुछ नया प्लान करना शुरू कर देता है. वह हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि इस साल का उसका क्रिएटिव आइडिया पिछले साल के काम से अलग हो. इस साल भी कुछ अलग नहीं था; यह अनोखा क्रिएशन सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा की मूर्ति बनाने के आइडिया से पैदा हुआ था. ' जयमाल्या मंडल की मां अपने बेटे की बहुत तारीफ करती हैं. असीमा मंडल कहती हैं, 'हर साल दुर्गा पूजा के दौरान, जयमाल्या अपने आइडिया के आधार पर अलग-अलग चीजें बनाता है. जैसे, इस साल उसने मुझसे बाजार से सूखी लाल मिर्च और फेविक्विक गोंद खरीदने को कहा. मैंने उसके लिए ये सब खरीदा, और फिर, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, उसने सूखी मिर्च से दुर्गा की मूर्ति बनाई. पिछले वर्षों में, उसने माचिस की तीलियों, तेजपत्ता और बेल के पत्तों जैसी चीजों का इस्तेमाल करके दुर्गा की मूर्तियां बनाई हैं. उसमें बचपन से ही कला के प्रति जुनून रहा है. त्योहारों के मौसम में, जब कारीगर आमतौर पर मिट्टी, पुआल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और अलग-अलग सजावटी चीजों का इस्तेमाल करके देवी दुर्गा को सजाते हैं, तो जयमाल्या की पहल इन पारंपरिक तरीकों से हटकर एक संदेश देती है. उन्होंने एक बार फिर दिखाया है कि कला के लिए हमेशा महंगी चीजों या फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती; बल्कि, अपनी सोच और लगन से कुछ नया बनाया जा सकता है. इसलिए, इस साल सोनारपुर में देवी दुर्गा की पूजा के साथ इस नौजवान का इनोवेटिव क्रिएशन पर भी लोगों का ध्यान खींचेगा. जयमाल्या मंडल और उनका परिवार अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पूरी तरह से सूखी लाल मिर्च से बनी यह मूर्ति भक्तों को कितना पसंद आएगी।

परिवार का मुखिया था 45 साल का हमलावर

गर्भवती की एक साल की बेटी समेत आठ लोगों को मारा, वारदात से पुलिस भी सन्न

एरी (अमेरिका), एजेंसी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी में सामूहिक गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में एक साल की बच्ची, उसकी गर्भवती मां और महिला का पांच साल का बेटा भी शामिल हैं। रविवार को बच्ची के पिता ने कहा कि हमलावर परिवार का मुखिया था। वह एक दादा भी था। वह कभी परेशान या असामान्य व्यवहार करता नहीं दिखा।जूलियस विंडहैम ने शुक्रवार को हुई गोलीबारी के पीड़ितों की याद में बने स्मारक के पास खड़े होकर यह बात कही। उनकी एक साल की बेटी अमारियाना भी इस हमले में मारी गई। बच्ची की मां गर्भवती थी। महिला का पांच साल का बेटा और गर्भ में पल रहा बच्चा भी मारे गए। विंडहैम ने कहा, मुझे लगता है कि उसका सामान्य दिखना सिर्फ दिखावा था। वह हर दिन मुस्कुराता था और सामान्य व्यवहार करता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है।45 वर्षीय हमलावर ने खुद भी अपनी जान ले ली। अधिकारियों ने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, एरी के पुलिस प्रमुख रिक लोराह ने बताया कि हमलावर का मारे गए आठ लोगों में से सात से पारिवारिक रिश्ता था। आठवीं मृतक महिला की दोस्त थी। पुलिस ने पीड़ितों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए हैं।

घर के बाहर मिलीं दो महिलाओं की लाशें:रविवार को शोक मनाने पहुंचे लोगों ने उस घर के बाहर मोमबत्तियां, फूल और खिलौने रखे, जहां शुक्रवार शाम करीब पांच बजे से कुछ पहले हमलावर ने गोलियां चलाई थीं। विंडहैम ने ऐसी टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें थीं। उस पर लिखा था- हमेशा मेरे दिल में रहोगे। विंडहैम ने कहा, मैं इस समय किस दौर से गुजर रहा हूं, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपने समुदाय, अपने परिवार, बेटियों, बेटों और सभी लोगों के लिए मजबूत बने रहना होगा। पुलिस प्रमुख लोराह ने बताया कि जांचकर्ताओं को वीडियो और ऑडियो सबूत मिले हैं। इनमें घर के अंदर से धीमी आवाज में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दीं। इसके कुछ ही समय बाद दो महिलाएं वहां पहुंचीं। वे बेहद परेशान थीं और दरवाजा पीटने लगीं। इसके बाद हमलावर घर से बाहर आया। उसने दोनों महिलाओं पर गोली चलाई, जब वे उसकी ओर भाग रही थीं। फिर वह वापस घर के अंदर चला गया।मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को घर के बाहर दोनों महिलाओं के शव मिले। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन और रोबोट की मदद ली। फिर अधिकारी घर के अंदर दाखिल हुए। पहली मंजिल पर पांच साल के लड़के और एक साल की बच्ची के शव मिले। सीढ़ियों के पास दो अन्य महिलाओं और दो युवकों के शव मिले। हमलावर दूसरी मंजिल पर मिला। पुलिस प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान में मैं यह नहीं बताऊंगा कि घर के अंदर पुलिस अधिकारियों ने क्या देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा समुदाय समझे कि यह घटना कितनी गंभीर थी। इस त्रासदी का इसमें शामिल लोगों और पूरे समुदाय पर कितना गहरा असर पड़ा है।

फिलीपीन में बच्चों के यौन शोषण का खौफनाक नेटवर्क

कैमरे के सामने परोसा जा रहा बचपन

मनीला/वॉशिंगटन, एजेंसी। डिजिटल क्रांति के दौर में जहां दुनिया एक-दूसरे के करीब आई है, वहीं तकनीक का एक ऐसा घिनौना और खौफनाक चेहरा भी सामने आ रहा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। द्वीपीय देश फिलीपीन में गरीबी का फायदा उठा मासूमों को बाल यौन शोषण सामग्री में बदला जा रहा है। उन्हें अपने देश में यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है और अमीरों का शौक पूरा करने के लिए मीलों दूर स्थित शहरों में सीधे प्रसारित किया जाता है। सीएनएन की एक खोजी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों में बैठे लोग इसके बदले में बड़ी रकम खर्च करते हैं। फिलीपीन इस अवैध और खौफनाक ऑनलाइन नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। 13 वर्ष की केट (बदला नाम) की कहानी इस भयावह सच्चाई को बयां करती है। कोविड-19 के दौरान जब केट के पिता की नौकरी चली गई और परिवार पाई-पाई को मोहताज हो गया तो परिवार को भुखमरी से बचाने के नाम पर उसकी गोद ली गई बड़ी बहन ने ही उसे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। शुरुआती दिनों में केट से केवल विदेशी ग्राहकों के साथ बातचीत बातचीत का नाटक करने को कहा गया। लेकिन धीरे-धीरे मांगें बदलती गईं और ऐसे खौफनाक और हिंसक कृत्यों की मांग की जाने लगी, जिनकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

अपने ही कर रहे सौदा...एिन्क्रप्टेड एप्स से मिला बढ़ावा: बच्चों का सौदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार वाले ही होते हैं। फिलिपिनो पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दलालों में बड़ी संख्या उन माताओं की है, जिन्होंने आर्थिक तंगी के आगे अपने बच्चों का सौदा कर दिया। बच्चों का शोषण करने वाले खरीदार समाज के हर वर्ग से आते हैं। इनमें कॉलेज के छात्र, बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट कर्मचारी से लेकर जलवायु सलाहकार और पढ़े-लिखे पेशेवर तक शामिल हैं। कई आरोपी तो ऐसे हैं जो खुद शादीशुदा हैं और जिनके घर में बच्चे व नाती-पोते हैं।

अगले 73 वर्षों में धरती से मिट सकता है इंसानों का नामोनिशान लैंसेट की रिपोर्ट में डराने वाला दावा

वाशिंगटन , एजेंसी। साल 2100 तक धरती से इंसान विलुप्त हो सकते हैं। यह दावा हुआ है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन लैंसेट की एक रिपोर्ट में। वैश्विक जोखिम के विश्लेषण से जुड़ी इस रिपोर्ट में अगली सदी तक मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस रिपोर्ट में जिन कारणों को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक करार दिया गया है, उनमें परमाणु युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को उच्च स्तर पर रखा गया है। इसके साथ ही 17 अन्य खतरों को इंसानों की विलुप्ति के संभावित कारण के तौर पर शामिल किया गया है। आइये जानते हैं कि जिस लैंसेट रिपोर्ट में सन 2100 तक इंसानों के विलुप्त हो जाने का डर जताया गया है, वह क्या है और उसे तैयार किसने किया है इसमें इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा किन चीजों से

बताया गया है अलग-अलग क्षेत्रों के लिए इस रिपोर्ट में खतरे पैदा होने की क्या वजह बताई गई है

इंसानों की विलुप्ति का खतरा बताने वाली रिपोर्ट क्या, किसने तैयार की: इंसानों पर विलुप्ति का खतरा बताने वाली इस रिपोर्ट को 21वीं सदी में स्वास्थ्य के लिए वैश्विक खतरों पर लैंसेट आयोग की ओर से तैयार किया गया है। यह अध्ययन प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित हुआ है।

यह रिपोर्ट क्या है: इस रिपोर्ट में अगले 73 वर्षों (वर्ष 2100 तक) के दौरान मानव स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए 17 प्रमुख और विनाशकारी खतरों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एआई का गलत इस्तेमाल, जैसे- जैविक हथियार बनाना या परमाणु संघर्ष साल 2100 तक इंसानों के लिए विलुप्त होने का खतरा पैदा करते हैं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यूं तो इस विलुप्ति की घटनाओं की संभावना कम है, लेकिन अगर ये होता है तो इनका प्रभाव पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा। जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता में कटौती, बाल कुपोषण, वायु प्रदूषण, मोटापा और महामारियों को भी प्रमुख खतरों में शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है: इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य, विज्ञान और वैश्विक नीति से जुड़े 35 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम (आयोग) ने तैयार किया है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के निदेशक और कमीशन के सह-अध्यक्ष प्रो. क्रिस्टोफर मरे इसके सह-अध्यक्ष रहे। डॉ. नतालिया कानेम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की पूर्व कार्यकारी निदेशक और कमीशन की सह-अध्यक्ष हैं।यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) में संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के प्रोफेसर इब्राहिम अबूबकर भी इस आयोग के प्रमुख सदस्य हैं।

इंसानों की विलुप्ति के पीछे क्या हो सकती है वजह, खतरा क्यों: साल 2100 तक इंसानों की संभावित विलुप्ति का जोखिम उच्चतम स्तर पर पहुंचने के दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। 1. एआई का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल वजहः रिपोर्ट में कहा गया है कि वजह उन्नत एआई तकनीक का दुरुपयोग घातक जैविक हथियार तैयार करने के लिए किया जा सकता है। खतरा क्योंः अगर एआई की मदद से ऐसा खतरनाक जैविक एजेंट या वायरस विकसित हो जाता है जो अनियंत्रित हो जाए, तो यह दुनिया भर में फैलकर पूरी मानव जाति के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है।

संक्षिप्त समाचार

धीरेन्द्र शास्त्री के मैहर प्रवास को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज, कार्यक्रम से एक दिन पहले तैनात होगा पुलिस बल

मीडिया ऑडीटर,मैहर (निप्र)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तीन दिवसीय मैहर प्रवास को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है पुलिस अधिकारियों ने आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की है। आईजी गौरव राजपूत ने बताया कि पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम मैहर स्थित केजेएस में आयोजित होगा। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की जा चुकी है इसमें सुरक्षा संबंधी आवश्यक इंतजामों और श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई आईजी गौरव राजपूत के अनुसार कार्यक्रम शुरू होने से एक दिन पहले पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी, ताकि आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जा सके पुलिस प्रशासन का प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तीन दिवसीय प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया जा रहा है। आयोजन स्थल के आसपास भी सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सतर्कता बरती जाएगी।

● यातायात व्यवस्था पर रहेगा विशेष ध्यान:

कार्यक्रम में संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की आवाजाही के दौरान जाम की स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने की तैयारी है। पुलिस अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा के साथ यातायात प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया।

● अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर बढ़ाई सतर्कता:

पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मैहर प्रवास को देखते हुए पुलिस प्रशासन आयोजन से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने में जुटा है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है ताकि तीन दिवसीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके आईजी गौरव राजपूत ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम से पहले पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है हालांकि पुलिस बल की संख्या, यातायात मार्ग में बदलाव और अन्य विस्तृत व्यवस्थाओं के संबंध में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

ओम सोनेजा और मनीषा सोनेजा के निधन से सिंधु विकास समिति में शोक, सभा आयोजित कर दी श्रद्धांजलि

मीडिया ऑडीटर,सतना (निप्र)। समाजसेवी एवं सिंधु विकास समिति के सक्रिय सदस्य ओम सोनेजा और उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा सोनेजा के आकस्मिक निधन की खबर से समिति परिवार में शोक की लहर छा गई दोनों के निधन पर सिंधु विकास समिति के सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए समिति कार्यालय में शोकसभा आयोजित की इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की शोकसभा में सदस्यों ने ओम सोनेजा और मनीषा सोनेजा के निधन को समाज एवं समिति के लिए अपूरणीय क्षति बताया उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की समिति परिवार की ओर से प्रार्थना की गई कि ईश्वर दोनों पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस असहनीय दुख से उबरने का संबल प्रदान करें।

समिति सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि: शोकसभा में समिति के संरक्षक श्रीचंद मनवानी, गोपी गेलानी, मनोहर डिगवानी, विनोद गेलानी, ज्ञान खटवानी, इन्द्रलाल आडवाणी, श्रीचंद शीतलानी, घनश्याम मंघरानी, मनीष ठेकवानी, संजय वाधवानी, महेश रवलानी, गंगाराम सचदेव, दिलीप सोनी, मनोज सुखदानी, जितेंद्र गावरी, अमित कामरानी, रंजीत सेनानी, गोपीचंद कापड़ी, बसंत खन्नी, विजय जग्यासी, कमल पुरस्वानी, अशोक चांदवानी, राजकुमार साधवानी, सुधीर आहूजा, केशव माखीजा, दीपक वाधवानी, अमित घोषवानी, अनिल मोटवानी और पंकज आहूजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सिंगरौली में चोरी के शक में 3 नाबालिगों से मारपीट, आधा सिर मुंडवाने का आरोप

मीडिया ऑडीटर,सिंगरौली (निप्र)। जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में मोटर चोरी के शक में तीन नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट करने और उनके आधे सिर के बाल मुंडवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि 1 अक्टूबर को बच्चों को जबरन ले जाकर बंधक बनाया गया और अपमानित किया गया। परिजनों के मुताबिक, घटना के बाद बच्चे डरे हुए हैं और स्कूल जाना छोड़ दिया है। परिवार ने बरगवां थाने में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एसपी कार्यालय और अजाक थाने में शिकायत की। एसपी शियाज केएम ने बरगवां थाना प्रभारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में सीधी को राष्ट्रीय सम्मान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौंपी ट्रॉफी

फसल कटाई के बाद उपज के भंडारण में उत्कृष्ट कार्यों को मिली राष्ट्रीय पहचान, कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्राप्त किया सम्मान

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मध्यप्रदेश के सीधी जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जिले को यह सम्मान फसल कटाई के बाद कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ाने और बेहतर प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है इस उपलब्धि को जिले में कृषि अधोसंरचना के विकास और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के रूप में देखा जा रहा है कार्यक्रम में उप संचालक कृषि आरएस गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक शैलेन्द्र गौतम, अनुविभागीय कृषि अधिकारी अंकिता तिवारी तथा प्रगतिशील कृषक विपिन शुक्ला उपस्थित रहे।

देश के 100 चयनित जिलों में शामिल है सीधी: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल इसके तहत देश के 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से काम किया जा रहा है सीधी जिले में भी योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है योजना के तहत कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, कृषि ऋण की उपलब्धता और कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण जैसे प्रमुख उद्देश्यों पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एफपीओ और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा: योजना के डैशबोर्ड पर उपलब्ध अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में आठ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एवं सहकारी संस्थाओं को सहयोग दिया गया है इसके अलावा एक बल्क मिल्क कूलर स्थापित किया गया और आठ डेयरी सहकारी समितियों एवं मिल्क पूलिंग पॉइंट का संचालन दर्ज किया गया जिले में 15 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायता मिली जिनमें एक महिला सूक्ष्म उद्यम भी शामिल है। इन प्रयासों से कृषि आधारित व्यवसायों, दुग्ध संग्रहण एवं शीतलन सुविधाओं और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।

विभागीय समन्वय से कृषि विकास को गति: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी, सिंचाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है गुणवत्तापूर्ण बीज, किसान प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है फसल कटाई के बाद उपज का सुरक्षित भंडारण होने से गुणवत्ता बनाए रखने, नुकसान कम करने और किसानों को उपज के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है इसी दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सीधी जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

रीवा सीएमएचओ कार्यालय के बाबू पर रिश्वत लेने के आरोप, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय रीवा की स्थापना शाखा में पदस्थ बाबू मनोज तिवारी पर कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी के अनुसार इस संबंध में कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया है उन्होंने चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर सीएमएचओ कार्यालय के सामने गांधीवादी तरीके से धरना दिया जाएगा।

छह लाख के एरियर के बदले पांच हजार लेने का आरोप: ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी के लगभग छह लाख रुपये के एरियर भुगतान से संबंधित काम के लिए कथित तौर पर पांच हजार रुपये दिए गए थे उनके अनुसार 24 अगस्त को एरियर निकलवाने के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने स्थापना शाखा का काम देख रहे मनोज तिवारी को 500-500 रुपये के 10 नोट दिए थे यूनियन का दावा है कि रकम देते समय पांच हजार रुपये होने की बात भी स्पष्ट रूप से कही गई थी इसके बाद संबंधित कर्मचारी का एरियर निकलवाने का भरोसा दिलाया गया हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है मामले में जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ईएल स्वीकृति के नाम पर भी वसूली का आरोप: यूनियन ने स्थापना शाखा में अर्जित अवकाश (ईएल) स्वीकृत कराने के नाम पर भी कथित रूप से रुपये लेने का आरोप लगाया है। त्रिपाठी के मुताबिक 7 अक्टूबर को दो नर्सिंग ऑफिसरों से ईएल स्वीकृत कराने के लिए 500-500 रुपये, यानी कुल एक हजार रुपये लिए जाने का आरोप है।यूनियन ने इन दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर शिकायत में बताए गए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कराने की मांग की है ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कर्मचारियों को एरियर भुगतान और अर्जित अवकाश जैसी वैधानिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की अनुचित मांग का सामना नहीं करना चाहिए।

सीधी में मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू, बैगा जनजातीय परिवारों को घर के पास मिलेगा इलाज

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर कुसमी के लिए किया रवाना, दूरस्थ गांवों में जांच, उपचार और दवाइयों की मिलेगी सुविधा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले बैगा जनजातीय परिवारों सहित अन्य ग्रामीणों को अब घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने राजस्थान से प्राप्त अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर कुसमी के लिए रवाना किया इस यूनिट के माध्यम से दुर्गम गांवों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इस अवसर पर देव कुमार सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल यूनिट का स्टाफ मौजूद रहा सांसद ने यूनिट में उपलब्ध चिकित्सकीय उपकरणों, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों का निरीक्षण किया साथ ही यूनिट के नियमित एवं प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सेवा संकल्प अभियान के तहत पहल: मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप किया जा रहा है अभियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है इस पहल से उन ग्रामीण परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें दूरी आवागमन के साधनों की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल दूरी या संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए बैगा जनजातीय समुदाय सहित जरूरतमंद परिवारों को समय पर जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने यूनिट के नियमित संचालन पर जोर देते हुए कहा कि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कुसमी विकासखंड के दूरस्थ गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे इन शिविरों में मरीजों की जांच, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाओं का वितरण किया जाएगा।

पूर्व आईएफएस डॉ. एसपीएस तिवारी बने हिंदू धर्म परिषद के संरक्षक, अटल पार्क गरबा फेस्टिवल को भव्य बनाने का दिया भरोसा

17 से 19 अक्टूबर तक होगा गरबा फेस्टिवल-2026 का आयोजन, संगठन पदाधिकारियों ने जताई खुशी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। हिंदू धर्म परिषद ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी आयोजनों को भव्य स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिषद के संस्थापक नारायण डिगवानी, आजीवन संरक्षक अविराज और अध्यक्ष संजय तिवारी 'मुन्नू' की अनुशंसा पर संगठन प्रभारी अवधेश श्रीवास्तव ने पूर्व नगर निगम आयुक्त एवं भोपाल के पूर्व सीसीएफ डॉ. एसपीएस तिवारी (आईएफएस) को परिषद के संरक्षक मंडल का सदस्य बनाने की घोषणा की है उनके संरक्षक मंडल में शामिल होने पर संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है डॉ. एसपीएस तिवारी लंबे समय से धार्मिक एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। परिषद को उम्मीद है कि उनके अनुभव, मार्गदर्शन और सहयोग से संगठन की गतिविधियों को और विस्तार मिलेगा उनके जुड़ने से आगामी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को बेहतर ढंग से संचालित करने में भी सहायता मिलेगी।

गरबा फेस्टिवल को भव्य बनाने में करेंगे सहयोग: संरक्षक मंडल का सदस्य बनाए जाने पर डॉ. एसपीएस तिवारी ने परिषद के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी 17 से 19 अक्टूबर तक अटल पार्क में आयोजित होने वाले गरबा फेस्टिवल-2026 को भव्य बनाने के लिए वह पूर्ण सहयोग करेंगे हिंदू धर्म परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं गरबा फेस्टिवल के माध्यम से धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहित करने के साथ लोगों को उत्सव से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा आयोजन को सफल बनाने के लिए परिषद के सदस्य और पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

वरिष्ठजनों ने जताई खुशी, दी बधाई: डॉ. तिवारी को संरक्षक मंडल में शामिल किए जाने पर परिषद के मार्गदर्शक डॉ. सीबी शुक्ला, डॉ. केके परोहा, डॉ. ज्योति सिंह, डॉ. नरेश बजाज और विजय मोहन तिवारी सहित संस्था के अन्य सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया सभी ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन से परिषद की गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी गरबा फेस्टिवल के आयोजन प्रभारी हिमांशु सिंह सेंगर ने डॉ. एसपीएस तिवारी के संरक्षक मंडल में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनुभवी एवं कर्मठ व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलने से गरबा फेस्टिवल को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। परिषद का प्रयास है कि 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप दिया जाए।

सीधी में भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, सांसद और जिलाध्यक्ष रहे मौजूद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया कार्यक्रम में सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान मौजूद रहे हालांकि, प्रदर्शन में अपेक्षाकृत कम संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और वाटर कैनन भी खड़ी की गई थी लेकिन पुतला दहन के दौरान पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया भाजपा ने यह प्रदर्शन कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम से जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवाद को लेकर किया भाजपा नेताओं का आरोप है कि इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।इसी मुद्दे पर पार्टी राहुल गांधी से जवाब मांग रही है प्रदर्शन के दौरान सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे दूसरों को नसीहत देते हैं लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं के मामलों में कार्रवाई नहीं करते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अपने सांसद से जुड़े विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं।

संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में दमखम दिखाने रीवा रवाना हुआ सीधी का दल

जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को किया रवाना, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की दी शुभकामनाएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए सीधी जिले के खिलाड़ियों का दल रीवा के लिए रवाना हो गया जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता में खेल भावना, अनुशासन और समर्पण के साथ भाग लेने की अपील की रीवा में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सीधी जिले के खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी खेल क्षमता साबित करने और संभाग स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया।

अनुशासन और खेल भावना के साथ करें प्रदर्शन: खिलाड़ियों को रवाना करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं खेलों से शारीरिक क्षमता के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना का विकास होता है उन्होंने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना बनाए रखने और पूरे समर्पण के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने उम्मीद जताई कि सीधी जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तथा जिले को गौरवान्वित करेंगे उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतियोगिता में जीत के साथ-साथ अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार भी महत्वपूर्ण है संभाग स्तरीय प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और अन्य जिलों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करती है ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है और उन्हें आगे की खेल प्रतियोगिताओं के लिए अनुभव प्राप्त होता है। सीधी जिले के खिलाड़ियों का दल रीवा रवाना होने के दौरान उत्साह का माहौल रहा खिलाड़ियों को उम्मीद है कि वे प्रतियोगिता में अपने कौशल, मेहनत और टीम भावना का बेहतर प्रदर्शन करेंगे शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है संभाग स्तर पर सीधी जिले का प्रतिनिधित्व करने जा रहे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है जिला शिक्षा अधिकारी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने और खेल भावना का परिचय देने के लिए प्रोत्साहित किया।

कॉकरोचों के डर से किलेबंदी

संपादकीय

देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे दृश्य हमने युद्धों के दौरान भी नहीं देखे। 1984 के सिख-विरोधी दंगे बेहद भयावह और जानलेवा थे। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी तालाबंदी थी, लेकिन नागरिक अधिकार तब भी जिंदा थे। 10 अक्तूबर, 2026 को इतिहास में एक काली, डरावनी, दमनकारी तारीख के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने सड़कों पर कीलें गाड़ दी थीं, ताकि कोई गाड़ी उन रास्तों से गुजरे, तो टायर में पंक्चर हो जाए। यह कैसा लोकतंत्र है? 7000 से अधिक युवाओं और कुछ नेताओं-सांसदों को हिरासत में लिया गया। रात होने लगी, तो उन्हें छोड़ भी दिया गया। राजधानी दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई, सीमाएं लगभग सील कर दी गई, ड्रोन उड़ते देखे गए मानो किसी बाहरी आक्रमण या आतंकी हमले की आशंका हो! मानो कोई विदेशी आक्रांता हमारे देश को लूटने आ रहा हो! मेट्रो ट्रेन के 45 स्टेशन बंद किए गए। न प्रवेश, न ही निकास और न ही इंटरचेंज...! करीब 62 लाख लोग हररोज मेट्रो के जरिए इधर से उधर जाते हैं। कल्पना करें, कितने लोगों के पांव बांध दिए गए होंगे! करीब 250 ट्रेन रद्द कर दी गई, जो दिल्ली से अन्य राज्यों को जाती थीं और वहां से दिल्ली की ओर आती थीं। लाखों भारतीय 'बंधक' बनकर रह गए होंगे! बताया जाता है कि करीब 2 लाख रेल-यात्री प्रभावित हुए हैं। करीब 38,000 जवान, अर्द्धसैन्य बल और अन्य बलों के जवान दिल्ली में चारों तरफ तैनात कर दिए गए। नतीजतन 'जंतर-मंतर' तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन कनॉट प्लेस की गलियों में युवा नारेबाजी करते रहे। पुलिस से कई जगह टकराव भी हुए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वे भी देश की ताकत हैं। अहम सवाल है कि क्या कॉकरोचों से इतने खतरे या उपद्रवों की आशंकाएं थी? क्या खुफिया एजेंसियों ने भी ऐसी रपटें दी थीं कि कॉकरोच राजधानी में उत्पात मचा सकते हैं और काट कर जहर फैला सकते हैं? सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायिक पीठ ने कहा था कि मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं। मेट्रो, ट्रेनें, सड़कें, परिवहन आदि के कारण आम नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार धरने-प्रदर्शन की वैकल्पिक जगह तय कर सकती है। चूंकि सरकार और पुलिस ने सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियों को हल्के में लिया, लिहाजा अब 'अदालत की अवमानना' के तहत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को अदालत में तलब किया गया है। अदालत कठोर कार्रवाई करे, ताकि एक व्यापक संदेश जा सके। बहरहाल त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। इस दौरान औसतन 3-4 लाख लोग हररोज दिल्ली के बाजारों में आते हैं। करीब 5 लाख व्यापारी काम करते हैं। मेट्रो और ट्रेनें बंद कर दी गई, तो खरीददार दिल्ली तक कैसे आएंगे? पेट्रोल पंपों तक पर भीड़ बहुत कम देखी गई। होटल, रेस्तरां, सिनेमा की बुकिंग रद्द कर दी गई। व्यापार संगठनों का अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हुआ है! यह कैसी जन-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा है कि नागरिक ही पिस रहा है? यह धारणा मोदी सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। अंततः हम सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। क्या प्रदर्शनकारी कॉकरोच इतने खतरनाक और ताकतवर आंके गए हैं कि राजधानी दिल्ली को बंद, लगभग ठप, करने की नौबत आ गई? कॉकरोच जनता पार्टी कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, कुंठित और महत्त्वाकांक्षी युवाओं का समूह भर है, लेकिन युवाओं, खासकर जेन-जी, को एक ऐसा मंच मिल चुका है, जहां से वे अपना आक्रोश, गुस्सा और अपने मुद्दों को बयां कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक आज़ादी की रक्षा हो

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की सख्ती के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह बताता है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर संविधान द्वारा नागरिकों को मिली आजादी का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कोर्ट द्वारा हिरासत में रखे लोगों को रिहा करने, मेट्रो सेवाएं बहाल करने तथा इंटरनेट सुविधा यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश देकर कोर्ट ने साफ संदेश देने का प्रयास किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में एक मूलभूत अधिकार है, न कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा। उल्लेखनीय है कि गत दस अक्तूबर को कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ अन्य संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। जिसको रोकने के लिये दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए थे। इस दौरान सात हजार से अधिक लोगों को

हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल उठाये गए। लोगों ने जगह-जगह सड़कों पर अवरोधक लगाने, क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों पर बंदिश लगाने तथा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सख्ती को लेकर चिंता जाहिर की। कहा गया कि पुलिस ने एहतियाती दायित्वों से बढ़कर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। निस्संदेह, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। जब आंदोलन आदि के दौरान हिंसा होने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका हो तो आसन्न खतरों के मद्देनजर अधिकारियों की कार्रवाई करना बनता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इन अधिकारों का उपयोग कानून की सीमाओं में ही किया जा सकता है।

लेकिन सवाल है कि सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने पर लोगों को हिरासत में लेना, निर्धारित निषेधाज्ञा वाले इलाकों से बहुत दूर तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक सेवाओं पर रोक लगे तो क्या यह आम लोगों को दंड देने जैसा नहीं है? तभी शीर्ष अदालत ने कोर्ट-परिसर के आस-पास रोक लगाने वाले नोटिस भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए। जिससे नागरिक-अधिवक्ता बिना किसी बाधा के यहां पहुंच सकें। दरअसल, विपक्षी दल लोगों को हिरासत में रखने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। निस्संदेह, पुलिस को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। बेशक, प्रदर्शनकारियों के साथ ही कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। यह एक हकीकत है कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा विश्वसनीय जवाबों, खुली व निष्पक्ष जांच और संस्थागत आजादी पर ही निर्भर करता है। वहीं एक मजबूत लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि वह असंतुष्ट लोगों की शिकायतों को सुनें, असहमति का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाये रखें और अदालत के निर्देशों का सम्मान करें। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण सीमा-रेखा खींची है। इसी आलोक में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों में संविधान प्रदत स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। हालांकि, सीजेपी व विपक्ष के तेवरों को देखते हुए यह करना आसान भी नहीं होगा।

वनाधिकार कानूनः कागज पर हक, जमीन पर इंतजार

कुमार कृष्णन

जंगल को बचाने वाली पीढ़ियां आज अपने ही जंगल पर अधिकार साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। जिन आदिवासी और परंपरागत वनवासी समुदायों ने जंगलों के साथ जीना सीखा, उनकी रक्षा की और अपनी संस्कृति को प्रकृति के साथ विकसित किया, उन्हें आज भी अपनी जमीन और आजीविका के लिए कानूनी मान्यता का इंतजार करना पड़ रहा है। यह केवल प्रशासनिक उदासीनता का मामला नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय का विस्तार है, जिसे दूर करने के लिए वनाधिकार अधिनियम, 2006 बनाया गया था। कानून लागू हुए करीब दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन सवाल जस का तस है–क्या वनवासियों को उनका हक मिला, या अधिकारों की घोषणा के बाद उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं के हवाले छोड़ दिया गया?

9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन पर आयोजित दूसरे क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश को वनाधिकार पत्रों के डिजिटलीकरण, सरकारी अभिलेखों में उनके दर्जीकरण और लाभार्थियों को आजीविका योजनाओं से जोड़ने के अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सितंबर में बेंगलुरु में आयोजित पहला क्षेत्रीय सम्मेलन इसी समीक्षा प्रक्रिया की अगली कड़ी था।

सम्मेलन का उद्देश्य लंबित दावों के निपटारे में आने वाली बाधाओं को पहचानना और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के रास्ते तलाशना था। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि समीक्षा बैठकों से निकलने वाले निर्णय उन गांवों तक कब पहुंचेंगे, जहां लोग पीढ़ियों से जंगल पर निर्भर हैं? किसी सम्मेलन की सफलता अधिकारियों की प्रस्तुतियों या जारी निर्देशों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होनी चाहिए कि कितने वंचित परिवारों को अधिकार मिला और कितने समुदायों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव आया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक देशभर में 54,01,561 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए थे। इनमें 25,42,359 दावों के तहत अधिकार पत्र वितरित किए गए, 18,13,232 दावे खारिज हुए और 10,45,970 लंबित थे। ये आंकड़े राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मासिक प्रगति रिपोर्ट पर आधारित थे।

कोलकाता सम्मेलन से संबंधित विवरण में 31 अगस्त 2026 तक की स्थिति को मोटे तौर पर 54 लाख से अधिक प्राप्त दावों, लगभग 25 लाख जारी अधिकार पत्रों, करीब 11 लाख लंबित दावों और 18 लाख से अधिक खारिज दावों के रूप में बताया गया। जून और अगस्त की स्थितियां अलग-अलग तारीखों की हैं, इसलिए दोनों को एक ही समय के आंकड़े मानना उचित नहीं होगा। हालांकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

देशभर में लाखों दावों का लंबित रहना केवल प्रशासनिक आंकड़ा नहीं है। हर लंबित दावे के पीछे एक परिवार, उसकी आजीविका और उसके भविष्य का सवाल हो सकता है। इसी तरह, किसी दावे का खारिज होना भी अपने आप में अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यह जानना जरूरी है कि दावे किन कारणों से अस्वीकृत हुए, क्या आवेदकों को निर्णय की जानकारी मिली और क्या उन्हें अपील या पुनर्विचार का अवसर दिया गया। आवेदन का निपटारा कर देना और न्याय सुनिश्चित करना अलग-अलग बातें हैं।

वनाधिकार अधिनियम ने स्वीकार किया कि अनुसूचित जनजातियों और दूसरे परंपरागत वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है तथा उनके परंपरागत अधिकारों को पर्याप्त कानूनी मान्यता नहीं मिली। इस कानून का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत जमीन पर अधिकार देना नहीं, बल्कि समुदायों के परंपरागत वन संसाधनों पर अधिकारों को भी पहचानना है। इसके बावजूद क्रियान्वयन में व्यक्तिगत अधिकार पत्रों पर ध्यान केंद्रित रहने और सामुदायिक अधिकारों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलने का सवाल उठता रहा है।

दूरदराज के गांवों में रहने वाले वनवासियों के पास पुराने भूमि दस्तावेज हमेशा उपलब्ध नहीं होते। कई बार वन विभाग और राजस्व विभाग के अभिलेखों में जमीन की सीमाओं और उपयोग को लेकर अंतर होता है। ऐसी स्थिति में केवल कागजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना कानून के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। स्थानीय परंपराओं, उपलब्ध साक्ष्यों और जमीन के परंपरागत उपयोग को समझना भी जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जांच की जरूरत समाप्त हो जाए, बल्कि यह है कि जांच की प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो और दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रह जाए।

वनाधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के बीच अंतर समझना जरूरी है। व्यक्तिगत वनाधिकार पात्र परिवारों के मान्य अधिकारों से संबंधित है। सामुदायिक वनाधिकार के अंतर्गत गांव के लोगों के परंपरागत उपयोग से जुड़े संसाधनों और अधिकारों को मान्यता मिल सकती है। इनमें लघु वनोपज, चराई, जलस्रोतों और दूसरे पारंपरिक संसाधनों के उपयोग से जुड़े अधिकार शामिल हो सकते हैं।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसे संक्षेप में सीएफआरआर कहा जाता है, ग्रामसभा को परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले वन क्षेत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार आपस में संबंधित हैं, लेकिन दोनों एक ही श्रेणी नहीं हैं।

क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन से संबंधित विवरण के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश में 19,845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता प्राप्त थे। यह संख्या सीएफआरआर से संबंधित है, सभी प्रकार के सामुदायिक वनाधिकारों की कुल संख्या नहीं। इसके बावजूद यह सवाल महत्वपूर्ण है कि कितनी ग्रामसभाएं अपने परंपरागत वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में इन अधिकारों का वास्तविक इस्तेमाल कर पा रही हैं।

जंगल पर निर्भर समुदायों की आजीविका महुआ, शहद, औषधीय पौधों, जलस्रोतों और चराई जैसे संसाधनों से जुड़ी होती है। व्यक्तिगत अधिकार पत्र मिलने से पूरे गांव के परंपरागत वन संसाधनों पर सामूहिक अधिकार अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाता। ग्रामसभा को केवल आवेदन तैयार करने या दस्तावेज प्रमाणित करने वाली संस्था समझना कानून की भावना के विपरीत होगा। उसे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और वन संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन में प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए।

भूमि और वन अधिकारों के सवाल पर गांधीवादी कार्यकर्ता तथा एकता परिषद के संस्थापक पी. वी. राजगोपाल का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उनका जनांदोलन इस विचार पर आधारित रहा है कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच गरीबों, आदिवासियों तथा वंचित समुदायों की आजीविका और गरिमा से जुड़ी है। इस दृष्टिकोण में वन संरक्षण और समुदायों के अधिकारों को परस्पर विरोधी मानने की जगह उनके बीच संतुलन बनाने पर जोर है।

वास्तव में, जंगलों की रक्षा के नाम पर स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना न तो न्यायसंगत है और न ही टिकाऊ संरक्षण के हित में। सदियों से जंगलों के साथ रहते आए समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव को नजरअंदाज करके वन संरक्षण की कल्पना अधूरी है। लेकिन अधिकारों की मान्यता का अर्थ जंगलों की पारिस्थितिकी की अनदेखी करना भी नहीं है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें समुदायों के अधिकार, उनकी जवाबदेही और पर्यावरणीय संतुलन साथ-साथ आगे बढ़ें।

कोलकाता सम्मेलन में वनाधिकार पत्रों के डिजिटलीकरण और सरकारी अभिलेखों में उनके दर्जीकरण पर जोर देना उपयोगी है। लेकिन अधिकार पत्र जारी होने के बाद भी यदि संबंधित सरकारी अभिलेखों में अधिकार दर्ज नहीं होता, तो लाभार्थी को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटलीकरण से रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और लंबित मामलों की निगरानी में मदद मिलेगी, लेकिन तकनीक अपने आप न्याय नहीं दिला सकती। यदि मूल रिकॉर्ड में गलती है, तो उसे डिजिटल करने से गलती दूर नहीं होगी। इसलिए रिकॉर्ड में सुधार, निर्णयों की पारदर्शिता और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सहायता देने की व्यवस्था भी आवश्यक है।

झारखंड में अधिकारों की मान्यता, लेकिन हजारों दावे अब भी लंबित हैं।

झारखंड में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की स्थिति इस सवाल को और गंभीर बनाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में 12 अगस्त 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक राज्य में कुल 1,10,756 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए थे। इनमें 1,07,032 व्यक्तिगत और 3,724 सामुदायिक दावे शामिल थे। इस अवधि तक 61,970 दावों के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए थे, जिनमें 59,866 व्यक्तिगत और 2,104 सामुदायिक अधिकार पत्र थे। वहीं, 28,107 दावे खारिज हुए और 20,679 लंबित थे।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सामुदायिक अधिकारों को भी मान्यता मिली है। लेकिन 20,679 दावों का लंबित रहना और 28,107 दावों का खारिज होना गंभीर समीक्षा की मांग करता है। सवाल यह है कि किन जिलों में सबसे अधिक दावे लंबित हैं, अस्वीकृति के क्या कारण रहे और कितने आवेदकों को निर्णय के विरुद्ध अपील करने का वास्तविक अवसर मिला। मंत्रालय के उपलब्ध राज्यवार विवरण में लंबित और खारिज दावों का कुल आंकड़ा दिया गया है, लेकिन इन दोनों श्रेणियों का व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावों के अनुसार अलग-अलग ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्य में वनाधिकार कानून का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत जमीन पर अधिकार पत्र देना नहीं हो सकता। सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के माध्यम से ग्रामसभाओं को परंपरागत वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन में प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए। महुआ, शहद, तेंदूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज पर निर्भर समुदायों के लिए इन अधिकारों का सीधा संबंध आजीविका और आर्थिक स्वावलंबन से है। इसलिए राज्य सरकार को लंबित दावों के समयबद्ध निपटारे के साथ सामुदायिक दावों की पहचान, ग्रामसभाओं को तकनीकी सहायता और जारी अधिकार पत्रों को सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

झारखंड में सामुदायिक दावों का दर्ज होना और उनके तहत अधिकार पत्र जारी किया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इन संख्याओं से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ग्रामसभाओं को वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में प्रभावी अधिकार मिल चुके हैं। यह जानना भी जरूरी है कि कितने समुदाय अपने मान्य अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कितने गांवों में वन संसाधनों के प्रबंधन की योजनाएं ग्रामसभा की भागीदारी से तैयार हुई हैं। अधिकार पत्र जारी करने के साथ उनके व्यावहारिक इस्तेमाल की निगरानी भी होनी चाहिए।

बिहार में सामुदायिक दावों का शून्य होना सवाल खड़े करता है

बिहार की स्थिति इस संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक राज्य में 4,696 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए थे। इनमें 191 दावों के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए, 4,496 दावे खारिज हुए और नौ लंबित थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आंकड़ों में कोई सामुदायिक वनाधिकार दावा दर्ज नहीं था। जारी किए गए सभी 191 अधिकार पत्र व्यक्तिगत वनाधिकार की श्रेणी में थे।

बिहार में सामुदायिक वनाधिकार के दावों का शून्य होना गंभीर समीक्षा की मांग करता है। क्या संभावित पात्र समुदायों तक कानून की जानकारी पहुंची? क्या ग्रामसभाओं को दावे तैयार करने और जरूरी साक्ष्य जुटाने में सहायता मिली? क्या परंपरागत वन संसाधनों पर निर्भर गांवों की पहचान की गई? इन सवालों का जवाब गांव और जिला स्तर पर जांच के बाद ही मिल सकता है। सामुदायिक दावों का शून्य होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि राज्य में ऐसे अधिकारों के पात्र समुदाय नहीं हैं। यह जागरूकता, पात्रता की पहचान और प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा की जरूरत की ओर भी संकेत करता है।

इसी तरह, बिहार में 4,496 दावों का खारिज होना भी गंभीर सवाल उठाता है। राज्य सरकार को अस्वीकृति के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र परिवार केवल प्रक्रियागत कमियों के कारण अपने अधिकार से वंचित न रहें। वन, राजस्व और जनजातीय कल्याण विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ ग्रामसभाओं को जरूरी कानूनी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

झारखंड और बिहार के आंकड़ों में अंतर दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना की जरूरत बताता है। झारखंड में सामुदायिक दावों और अधिकार पत्रों की मौजूदगी के बावजूद उनके प्रभावी इस्तेमाल, लंबित मामलों और खारिज दावों की समीक्षा जरूरी है। बिहार में पहली चुनौती पात्र समुदायों की पहचान, कानून के प्रति जागरूकता और सामुदायिक दावों की प्रक्रिया को मजबूत करना है। हालांकि, केवल आंकड़ों के आधार पर दोनों राज्यों में पात्र समुदायों की वास्तविक संख्या या कानून के क्रियान्वयन की पूरी तस्वीर तय नहीं की जा सकती। इसके लिए जिला और ग्रामसभा स्तर पर विस्तृत समीक्षा जरूरी है।

राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के आंकड़े अलग-अलग सार्वजनिक किए जाने चाहिए। कितने दावे प्राप्त हुए, कितने स्वीकार किए गए, कितने खारिज हुए, कितने लंबित हैं और कितने मान्य अधिकार सरकारी अभिलेखों में दर्ज हुए–इनकी नियमित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लंबित मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय हो और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। खारिज दावों की समीक्षा और पात्र परिवारों के लिए अपील की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कोलकाता सम्मेलन की असली सफलता इसी से तय होगी कि लंबित दावों पर समयबद्ध निर्णय हुए या नहीं, गलत तरीके से खारिज मामलों की समीक्षा हुई या नहीं, ग्रामसभाओं को वास्तविक अधिकार मिले या नहीं और वनाधिकार पत्रों का लाभ संबंधित परिवारों तक पहुंचा या नहीं। समीक्षा का उद्देश्य केवल प्रशासनिक प्रगति दर्ज करना नहीं, बल्कि कानून की मूल भावना को जमीन पर उतारना होना चाहिए। वनाधिकार कानून का सवाल केवल जमीन का नहीं, सम्मान, आजीविका और लोकतांत्रिक न्याय का भी है।

राजधानी दिल्ली में आर-पार की जंग, न्यायपालिका कसौटी पर

संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में एक धारणा बन गई है, वह सब एक विचारधारा के लोग हैं। जिन्हें सुनियोजित रूप से प्रमुख पदों पर बिठाया गया है। यहां तक कि स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी जो नियुक्तियां पिछले वर्षों में की गई हैं, वह भी एक विचारधारा के लोगों की हैं। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार में भी यह चर्चा होने लगी है। भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े एक विचारधारा के लोग है। उन्हें ही सरकारी वकील और जजों के रूप में नियुक्त किया गया है।

सनत जैन

भारत की राजधानी दिल्ली जंग का मैदान बन गई है। इस जंग में विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ-साथ कॉकरोच, वकील, पत्रकार और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, इतनी जल्दी इतनी तेजी के साथ इस तरह की जंग के हालात बनेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सत्ता की लड़ाई मानी जा सकती है, लेकिन आम आदमी, अधिवक्ता, पत्रकार, युवा और बच्चे यदि इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, तो यह समझना होगा कि कहीं कोई ना कोई बात तो है, जो इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आकर अपने अस्तित्व के लिये यह लड़ाई लड़ रहे हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, होई वही जो राम रचि राखा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं सरकार के पक्ष में आकर खड़ी हो गई हैं। यह सरकार की समर्थता है। सरकार को दोष भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर एकजुट हो रहे हैं। यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में एक धारणा बन गई है, वह सब एक विचारधारा के लोग हैं। जिन्हें सुनियोजित रूप से प्रमुख पदों पर बिठाया गया है। यहां तक कि स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी जो नियुक्तियां पिछले वर्षों में की गई हैं, वह भी एक विचारधारा के लोगों की हैं। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार में भी यह चर्चा होने लगी है। भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े एक विचारधारा के लोग है। उन्हें ही सरकारी वकील और जजों के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका भी सरकार को बचाने का काम कर रही है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वह सब सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिये अलग और विपक्ष के लिये अलग नियम-कानून हैं। लोगों को कहीं से भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जिसके कारण अब सड़कों पर जंग की स्थिति देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उसके बाद एसआईआर, चुनाव के पूर्व एवं चुनाव के दौरान जो भी मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन सब मामलों में न्यायपालिका ने सरकार को प्रत्यक्ष रूप से फेवर किया है। तारीख पर तारीख बढ़ाकर मामले को टाल दिया गया, सरकार जो चाहती थी, वह उसने कर लिया, संविधान और कानून का कोई पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट द्वारा जो भी आदेश पारित किए गए, उसमें सरकार के लिए एक चोर दरवाजा खोल दिया गया। इस चोर दरवाजे से सरकार बाहर निकलकर वह सब काम करती रही, जो वह करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार के दिन विशेष सुनवाई

की, उसके पहले भी जो सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका पालन दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। हर आदेश में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट कानून व्यवस्था के नाम पर अथवा आधा अधूरा फैसला देकर सरकार के लिए रास्ता छोड़ देती है। इसका दुरुपयोग सरकार और उसकी एजेंसियां कर रही हैं। हाल ही में जिस तरह से वकीलों, पत्रकारों को दिल्ली में अरेस्ट किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रेन बंद कर दी गई। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। 4 किलोमीटर क्षेत्र दिल्ली में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बैरिकेड लगा दिए, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया। दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध तरीके से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिये गए लोगों को कई घंटे तक बसों में घुमाया गया। उन्हें मल-मूत्र त्यागने की भी सुविधा नहीं दी गई। हिरासत में जो हजारों लोग बंद थे, उन्हें खाना-पानी भी नहीं दिया गया। यह स्थिति पहली बार दिल्ली में देखने को मिली।

दिल्ली में 35 हजार से ज्यादा अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया है, जिसके कारण अब लोगों में सरकार के खिलाफ विद्रोह देखने को मिला रहा है। जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था, वह भी नाराज होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ अब वकील और बार से भी आवाज आने लगी है। सारे विपक्षी नेता राष्ट्रपति सहित हर दरवाजे को खटखटाकर आ गए हैं। अब अंतिम दरवाजा न्यायपालिका का है। सुप्रीमकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, मुख्य न्यायाधीश ने नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी सांसदों से मिलने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। उससे आम जनता को न्याय मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है, उसका पालन ना तो दिल्ली पुलिस कर रही है, नाही केंद्र सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल जिस तरह का पक्षपात कर रहा है। बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन प्रतिबंधित स्थान पर हो रहा है। दिल्ली पुलिस चुप है। वर्तमान स्थिति को जल्द नहीं संभाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सरकार मानेगी? इसको लेकर सभी के दिमाग में संदेह उत्पन्न हो रहा है। दिल्ली प्रेस क्लब में दिल्ली पुलिस घुस गई। आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, भगवान ही मालिक है। जिस तरह के हालात बन गये है, वह एक तरह से गृह युद्ध जैसे हैं। यदि ऐसा हुआ, तो इसका बड़ा भारी नुकसान होना तय है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की साख दांव पर लगी हुई है, उसको देखते हुए यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है, आने वाले समय में भारत को भारी दुष्परिणाम भोगना पड़ेंगे।

नवरात्रि-दशहरे पर अनूपपुर और कोतमा में भारी वाहनों की नो-एंट्री

15 से 20 अक्टूबर तक सुबह 6 से रात 12 बजे तक रहेगा प्रतिबंध जिलेभर में शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात

मीडिया ऑडीटर, अनूपपुर (निप्र)। नवरात्रि और दशहरा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए अनूपपुर जिला मुख्यालय और कोतमा के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है यह प्रतिबंध 15 से 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा अपर कलेक्टर बलवीर रमन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है पर्व के दौरान दुर्गा पंडालों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है प्रतिबंध का उद्देश्य यातायात का दबाव कम करना और आम नागरिकों के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है कानून-व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कलेक्टर रत्नाकर झा ने नवरात्रि और दशहरा पर्व के दौरान जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं अधिकारियों को दुर्गा प्रतिमाओं पूजा पंडालों और समारोह स्थलों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है अनूपपुर थाना क्षेत्र में तहसीलदार वेद प्रकाश सिंह, चचाई में नायब तहसीलदार ज्ञानदास पनिका और फुनगा चौकी क्षेत्र में नायब तहसीलदार कौशलेन्द्र शंकर मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है भालूमाड़ा में नायब तहसीलदार मंगलदास चक्रवर्ती, जैतहरी में तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा और वेंकटनगर में नायब तहसीलदार राजेंद्र दास पनिका की तैनाती की गई है कोतमा, बिजुरी और अमरकंटक में भी जिम्मेदारी तय कोतमा में तहसीलदार दशरथ सिंह और नायब तहसीलदार गुरुदास प्रसाद मेहरा बिजुरी में नायब तहसीलदार लवतेन्द्र सिंह तथा रामनगर में नायब तहसीलदार संतोष चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है राजेंद्रग्राम में तहसीलदार ईश्वर प्रधान और नायब तहसीलदार विशाल रत्नम, अमरकंटक में नायब तहसीलदार विनोद सिंह बरगाही तथा करनपठार में नायब तहसीलदार सोहनलाल कोल और रमाकांत तिवारी व्यवस्था संभालेंगे विसर्जन स्थलों पर भी रहेगी निगरानी प्रशासन ने दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित कुंडों और स्थलों पर कराने के निर्देश दिए हैं। विसर्जन स्थलों पर राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जबकि पुलिस के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहयोगी अधिकारी बनाया गया है संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे प्रशासन ने पर्व के दौरान शांति सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए हैं मजिस्ट्रेटों की सूची संक्षिप्त करेंवाहन प्रतिबंध का आदेश स्पष्ट करेंसमाचार को अधिक खबरनुमा बनाएं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से साकार हुआ सुनीता का विवाह का सपना

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह कई बार बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिलने से विवाह की राह आसान हो रही है मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम नवापारा निवासी सुनीता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में उनका विवाह संपन्न हुआ शासन की इस पहल से उन्हें जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिला सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई सुनीता की यह कहानी जरूरतमंद परिवारों के लिए शासकीय योजनाओं के महत्व को दर्शाती है महामाया मंदिर में 54 जोड़ों के साथ शुरू हुआ नया जीवन सुनीता का विवाह 10 फरवरी 2025 को खड़गवां स्थित महामाया मंदिर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न हुआ था इस आयोजन में कुल 54 जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे इन्हीं में ग्राम नवापारा की सुनीता भी शामिल थीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों के लिए विवाह संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई थीं सुनीता के लिए यह दिन जीवन की नई शुरुआत लेकर आया योजना के माध्यम से विवाह संपन्न होने से उनके परिवार को आर्थिक राहत मिली विवाह की आवश्यक व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से परिवार को आयोजन संबंधी खर्चों की चिंता से भी काफी हद तक राहत मिली सुनीता आज भी इस अवसर को अपने जीवन के यादगार पलों में शामिल करती हैं 50 हजार रुपये की सहायता से परिवारों को मिल रहा संबल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र जोड़ों के विवाह के लिए कुल 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है इसमें 35 हजार रुपये की राशि चेक के माध्यम से लाभार्थी जोड़े को प्रदान की जाती है, जबकि शेष 15 हजार रुपये विवाह संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं इनमें श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, उपहार, भोजन, मंडप, सजावट एवं अन्य व्यवस्था शामिल हैं योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है सामूहिक विवाह के माध्यम से एक ही स्थान पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है साथ ही जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सहभागिता के बीच सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कराने का अवसर मिलता है शासन के सहयोग से आसान हुई विवाह की राह,ाम नवापारा की सुनीता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर सहारा बनी योजना के माध्यम से विवाह संपन्न होने से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिला और विवाह की आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हुईं सुनीता ने बताया कि शासन की इस योजना का लाभ मिलने से वह बेहद खुश हैं।

सक्षम योजना से बदली चंपा देवी की तकदीर, पशुपालन बना कमाई का जरिया

1.80 लाख रुपये के ऋण से खरीदीं तीन गायें, अब चार गायों से दूध बेचकर परिवार को दे रहीं आर्थिक संबल

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम चैनपुर निवासी चंपा देवी कुशवाहा ने मेहनत और सरकारी योजना की मदद से आत्मनिर्भरता की राह तैयार की है कभी एक गाय से परिवार की दूध संबंधी जरूरतें पूरी करने वाली चंपा देवी अब पशुपालन को आमदनी का जरिया बना चुकी हैं छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना के तहत मिले 1 लाख 80 हजार रुपये के ऋण से उन्होंने तीन अतिरिक्त गायें खरीदीं अब दूध बेचकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रही हैं चंपा देवी पति अजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि पहले उनके पास एक गाय थी। उससे मिलने वाला दूध घर में ही इस्तेमाल हो जाता था पशुपालन का विस्तार करने की इच्छा थी लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी फरवरी 2026 में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित सक्षम योजना के तहत ऋण स्वीकृत होने के बाद उनके लिए यह संभव हो सका दूध बिक्री से होने लगी अतिरिक्त कमाई ऋण की राशि से तीन गायें खरीदने के बाद अब चंपा देवी के पास कुल चार गायें और दो बछिया हैं गायों की संख्या बढ़ने से दूध उत्पादन में भी इजाफा हुआ है परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद बचा दूध वह आसपास के घरों में बेचती हैं इससे होने वाली अतिरिक्त आमदनी दैनिक घरेलू खर्चों में मददगार बन रही है चंपा देवी अब भविष्य में अपने पशुपालन व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहती हैं उनका कहना है कि इस काम से परिवार को आर्थिक सहारा मिला है और स्वयं आय अर्जित करने से आत्मविश्वास भी बढ़ा है योजना बनी आत्मनिर्भरता का सहारा सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई चंपा देवी की कहानी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है उन्होंने योजना से मिली आर्थिक सहायता का उपयोग स्वरोजगार बढ़ाने में किया चंपा देवी ने सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया एक गाय से शुरू हुआ उनका सफर अब पशुपालन के जरिए परिवार की आमदनी बढ़ाने की मिसाल बन गया है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 55 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 55 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में रतलाम पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने ठगी की रकम में से करीब 20 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराए हैं दो आरोपियों को हैदराबाद और एक को कर्नाटक के धारवाड़ से गिरफ्तार किया गया पुलिस के अनुसार, फरियादी कुवैत में मोटर पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं और वर्तमान में रतलाम में रह रहे थे 15 सितंबर को आरोपियों ने फोन कर खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया मोबाइल नंबर के कथित आपराधिक इस्तेमाल और आईएसआई से जुड़े व्यक्ति से बातचीत का आरोप लगाकर उन्हें डराया गया इसके बाद व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर पुलिस वर्दी पहने व्यक्तियों से बात कराई गई सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी दस्तावेज भेजकर कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया गया आरोपियों ने जांच और सत्यापन के नाम पर बैंक खातों में रकम जमा कराने को कहा इस तरह फरियादी से आरटीजीएस के जरिए 55 लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा करा लिए गए शिकायत पर माणकचौक थाने में मामला दर्ज किया गया थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बैंक खातों तथा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस अब ठगी की रकम के लेनदेन और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह में विद्यार्थियों को दिया वन्यजीवों की सुरक्षा का संदेश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह 2026 के अंतर्गत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वनमंडल मनेन्द्रगढ़ द्वारा पीएम श्री विद्यालय चनवारीडांड में वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान विद्यार्थियों को वन्यप्राणियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व की जानकारी दी गई साथ ही सेवा संकल्प अभियान के तहत मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र के चैनपुर एवं फॉसिल्स पार्क में कुल 55 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया वन्यजीवों की सुरक्षा से ही बना रहेगा पर्यावरण संतुलन कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि वन्य प्राणी प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण आवश्यक है। अवैध शिकार, वनों की कटाई और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। विद्यार्थियों को वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने और उनके संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वन्यप्राणी दिखाई देने पर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। किसी वन्यजीव के घायल होने अथवा संकट में होने की स्थिति में तत्काल वन विभाग को सूचना देनी चाहिए। विद्यार्थियों से वन्यजीव संरक्षण का संदेश अपने परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की गई सेवा संकल्प अभियान में 55 पौधों का रोपण सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र में पौधारोपण किया गया। इसके तहत एकलव्य वनवासी कल्याण आश्रम, चैनपुर में 45 तथा फॉसिल्स पार्क, मनेन्द्रगढ़ में 10 पौधे लगाए गए। दोनों स्थानों पर कुल 55 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रहे उपस्थित कार्यक्रम में परिक्षेत्र अधिकारी मनेन्द्रगढ़ विश्वनाथ, परिक्षेत्र सहायक अशोक यादव एवं राम गोपाल सिंह सहित वन रक्षक इंद्र कुमार बंजारे, अशोक कुर्रे, मनोज सेन, देवगन सिंह एवं अनीता सिंह उपस्थित रहे।

अलीराजपुर में सीमेंट कंटेनर और ट्रक से 1,913 पेटी अवैध शराब जब्त

मीडिया ऑडीटर, भोपाल **(निप्र)।** मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,913 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है जब्त शराब की कुल मात्रा 16,712 बल्क लीटर बताई गई है पुलिस ने शराब परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे सीमेंट कंटेनर और ट्रक को भी जब्त किया है दोनों मामलों में कुल 2 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देशन में चांदपुर और उदयगढ़ थाना पुलिस ने की।

सीमेंट कंटेनर से मिली 1,426 पेटी शराब: चांदपुर पुलिस को राजस्थान पासिंग सीमेंट कंटेनर में अवैध शराब ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने खंडवा-बड़ौदा हाईवे पर वाहन रोककर तलाशी ली कंटेनर से 1,426 पेटी और 12,505 बल्क लीटर शराब बरामद हुई इस मामले में कंटेनर सहित करीब 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई और राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार, शराब पंजाब-हरियाणा सीमा के नरवाना क्षेत्र से भरकर राजस्थान के विभिन्न शहरों और मध्यप्रदेश के कई जिलों से होते हुए गुजरात के बड़ौदा ले जाई जा रही थी। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।

ट्रक छोड़कर भागा चालक, 487 पेटी बरामद: दूसरी कार्रवाई में उदयगढ़ पुलिस ने ग्राम तलावद की ओर से आ रहे ट्रक की घेराबंदी की पुलिस को देखकर चालक ग्राम जवानिया के तालाब के पास ट्रक छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान ट्रक में छिपाकर रखी गई 487 पेटी और 4,207 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद हुई ट्रक सहित करीब 54.97 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है दोनों मामलों में शराब के स्रोत, परिवहन से जुड़े लोगों और तस्करी नेटवर्क के संबंध में आगे की जांच जारी है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत से दीपक पाल की समस्या का हुआ समाधान, मिली ट्राई साइकिल

चलने-फिरने में परेशानी से जूझ रहे दिव्यांग दीपक को मिली राहत, अब आवागमन होगा आसान

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। शासन की जनकल्याणकारी सेवाएं जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान में मददगार साबित हो रही हैं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नगर पंचायत खोंगापानी निवासी दिव्यांग दीपक पाल की कहानी इसका उदाहरण है चलने-फिरने में परेशानी के कारण लंबे समय से आवागमन की कठिनाइयों का सामना कर रहे दीपक पाल ने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शासन-प्रशासन तक पहुंचाई। शिकायत के बाद प्रशासन ने उनकी समस्या के निराकरण की पहल की और उन्हें ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई यह कहानी बताती है कि शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है आवागमन की परेशानी से जूझ रहे थे दीपक हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत नगर पंचायत खोंगापानी निवासी दीपक पाल दिव्यांग होने के कारण दैनिक जीवन में आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में उन्हें परेशानी होती थी दैनिक जरूरतों और आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण था अपनी इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्या संबंधित अधिकारियों तक पहुंची इसके बाद शिकायत के निराकरण की दिशा में पहल करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई कलेक्टर ने प्रदान की ट्राइसाइकिल, आवागमन में मिलेगी सहूलियत कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दीपक पाल को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई लंबे समय से आवागमन की परेशानी का सामना कर रहे दीपक के लिए यह सहायता राहत लेकर आई है ट्राइसाइकिल मिलने से अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में सहूलियत होगी। साथ ही दैनिक जरूरतों से जुड़े कार्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी यह सहायता उनके लिए आवागमन का साधन होने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी।

JNU मामले पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की छात्राओं से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर सोमवार शाम शिवपुरी में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया माधव चौक पर एकत्रित महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शैलजा लवंगीकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, JNU की 11 छात्राओं ने बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की जांच के बाद 9 अक्टूबर 2026 को उन्हें प्रोफेसर पद से बर्खास्त किए जाने की खबर है इसके बाद 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की वहीं अकोइजम ने आरोपों को खारिज करते हुए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

कभी कुएं-हैंडपंप से लाते थे पानी, अब कमल सिंह के घर तक पहुंची नल की धार

जल जीवन मिशन ने बदली जवारीटोला की तस्वीर घर में पेयजल मिलने से रोज की मशक्कत हुई कम

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कभी पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कुएं और हैंडपंप के चक्कर लगाने वाले कमल सिंह को अब घर पर ही नल से पेयजल मिल रहा है जल जीवन मिशन के तहत मिली इस सुविधा से उनके परिवार की रोजमर्रा की परेशानी काफी हद तक दूर हो गई है मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्री के ग्राम जवारीटोला निवासी कमल सिंह के जीवन में आया यह बदलाव सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आया है केंद्र एवं राज्य शासन की जल जीवन मिशन योजना से घर तक पानी पहुंचने के बाद अब परिवार को पानी लाने के लिए पहले की तरह समय और मेहनत नहीं लगानी पड़ती कमल सिंह बताते हैं कि पहले उनके परिवार को पेयजल की व्यवस्था के लिए कुएं और हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था घर से बाहर जाकर पानी लाना रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा था इससे समय और मेहनत दोनों खर्च होते थे विशेषकर घरेलू जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था करना परिवार के लिए परेशानी भरा काम था जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में नल कनेक्शन मिलने के बाद यह स्थिति बदल गई है अब घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने से परिवार को कुएं और हैंडपंप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती इससे पानी लाने में लगने वाले समय और श्रम की बचत हो रही है कमल सिंह के अनुसार घर में नल से पानी मिलने की सुविधा ने परिवार की दिनचर्या को आसान बना दिया है पहले पानी लाने में लगने वाला समय अब दूसरे घरेलू कार्यों में उपयोग हो रहा है घर पर पेयजल उपलब्ध होने से परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में भी सहूलियत मिल रही है उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से मिली सुविधा उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है अब पानी की व्यवस्था के लिए पहले जैसी मशक्कत नहीं करनी पड़ती कमल सिंह ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से संचालित जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के जरिए निर्धारित गुणवत्ता वाला पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

संक्षिप्त समाचार

उर्मिला नदी में 10 फीट गोता लगाकर निकाल रहे बालू

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में उर्मिला नदी के हंसपुरा घाट पर मजदूर जान जोखिम में डालकर बालू निकाल रहे हैं। वे नदी के 5 से 10 फीट गहरे पानी में गोता लगाकर हाथों से तसलों में रेत भरते हैं। मजदूर सांस रोककर नदी की तलहटी से बालू निकालते हैं। फिर पानी से बाहर आकर सांस लेते हैं और दोबारा गोता लगाकर भरे तसले को ऊपर लाते हैं। इस तरह बालू निकालकर नदी किनारे जमा की जाती है। पानी की गहराई और बहाव के बीच यह काम मजदूरों के लिए खतरनाक है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं दिख रहे। क्षेत्र में नियमों के खिलाफ बालू निकालने के आरोप हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में गोयरा थाना क्षेत्र में बालू विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। घायल व्यक्ति ने पुलिस-प्रशासन पर अवैध खनन को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इसके बावजूद क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं हुई।

मजदूरों की सुरक्षा-निगरानी पर सवाल: नदी में गोता लगाकर बालू निकालने की इस प्रक्रिया में किसी दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की जान पर गंभीर खतरा हो सकता है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस और प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

रायसेन में 300 मिमी कम बारिश, धान सूखने लगी

गेहूं का रकबा 71 हजार हेक्टेयर घटेगा, चने की बोवनी बढ़ाने का लक्ष्य

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में इस साल सामान्य से करीब 300 मिलीमीटर कम बारिश हुई है, जिससे खेती और जलस्रोतों पर असर दिख रहा है। धान की फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, वह सूखने और पीली पड़ने लगी है। सिंचाई के लिए बिजली कटौती ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। सांची रोड स्थित कोड़ी नदी का पानी थम गया है, वहीं बेतवा नदी का जलस्तर भी घट गया है। कृषि वैज्ञानिक स्वप्निल दुबे के अनुसार, धान में बालियां निकलने के समय दो इंच पानी या पर्याप्त नमी जरूरी है, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। कम बारिश से ट्यूबवेल सिंचाई बढ़ी, बिजली खपत 60 लाख से 84-85 लाख यूनिट तक पहुंच गई। आपूर्ति कम होने से बिजली कंपनी कटौती कर रही है; किसानों को 10 घंटे की जगह तीन घंटे भी बिजली नहीं मिल रही। बारना डेम से नहरें अगले पांच दिन में बंद होंगी, जिससे रबी सीजन में सिंचाई का संकट गहरा सकता है। गेहूं का रकबा घटेगा, चने की बोवनी बढ़ेगी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने रबी सीजन 2026-27 में फसलवार रकबे में बदलाव किया है।

सफलता की कहानी

सरकारी सहयोग और मेहनत से संवारा भविष्य, डेयरी व्यवसाय से बढ़ी हितेंद्र सिंह दांगी की आय

मीडिया ऑडीटर,विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के ग्राम श्यामपुर गुदावल के युवा किसान श्री हितेंद्र सिंह दांगी ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उन्होंने सरकारी सहयोग और स्वयं के निवेश से डेयरी व्यवसाय शुरू किया। आज दो भैंसों से प्रतिदिन लगभग 14 लीटर दूध उत्पादन कर वे नियमित आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी सफलता ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। 'अगर इरादे मजबूत हों और सरकार का सहयोग मिल जाए, तो गांव में रहकर भी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की जा सकती है।' यह बात विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम श्यामपुर गुदावल के युवा किसान श्री हितेंद्र सिंह दांगी ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाई है।

रतलाम में जहरीली शराब तस्करी, चोरी की छह बाइक बरामद

कंजर गिरोह से पूछताछ में 17 वारदातें खुलीं, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

मीडिया ऑडीटर,रतलाम (निप्र)। रतलाम जिले में जहरीली कच्ची शराब की तस्करी के मामले में पकड़े गए तीन आरोपियों से वाहन चोरी की 17 वारदातों का खुलासा हुआ है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले कंजर गिरोह के इन आरोपियों से पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए कीमत की छह चोरी की बाइक जब्त की हैं। आरोपियों ने पूछताछ में 16 बाइक और एक महिंद्रा लोडिंग वाहन (छोटा हाथी) चोरी करने की बात कबूली है। आलोट और जावरा ग्रामीण अनुभाग की संयुक्त पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। रविवार रात ताल थाने में पुलिस ने मामले का खुलासा किया।

शराब तस्करी करते दो आरोपी पकड़े: आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया कि 11 अक्टूबर को पुलिस टीम ने अवैध कच्ची शराब की तस्करी करते हुए हरपाल कंजर और अर्जुन कंजर को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब और एक हीरो एचएफ डीलक्स बाइक जब्त की गई। इस मामले में ताल थाने में केस दर्ज किया गया।

जब्त बाइक के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने उसे ग्राम भाटखेड़ा से चोरी करना स्वीकार किया। इस चोरी का मामला कालूखेड़ा थाने में दर्ज है।

पूछताछ में दोनों ने अपने साथी लखन कंजर के साथ मिलकर 16 बाइक और एक महिंद्रा लोडिंग वाहन चोरी करने की बात कबूली।

● तीनों आरोपी झालावाड़ के रहने वाले

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरपाल (20), पिता धारिया कंजर; अर्जुन (19), पिता लखन कंजर; और लखन (22), पिता हरीलाल कंजर के रूप में की है। तीनों राजस्थान के झालावाड़ जिले के उन्हेल नागेश्वर थाना क्षेत्र के टोकड़ा गांव के निवासी हैं।

● ये छह बाइक जब्त कीं

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए कीमत की छह बाइक जब्त की हैं। इनमें शामिल हैं: हीरो एचएफ डीलक्स (MP43ZD4234), कालूखेड़ा थाने के मामले से संबंधित। हीरो एचएफ डीलक्स (MP13FS3119)। हीरो स्प्लेंडर, बिना नंबर; चेसिस नंबर MBLHAW129M416699। होंडा शाइन, बिना नंबर; चेसिस नंबर ME4JC734LH8012018। स्प्लेंडर प्लस, काले रंग की; इंजन और चेसिस नंबर घिसे हुए। स्प्लेंडर प्लस, काले रंग की; इंजन और चेसिस नंबर घिसे हुए।

● इन थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदातें

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने ताल थाना क्षेत्र से होंडा शाइन, आलोट से एचएफ डीलक्स और नामली थाना क्षेत्र से होंडा शाइन, महिंद्रा लोडिंग वाहन तथा बजाज प्लेटिना चोरी करने की बात कबूली है। इसके अलावा जावरा औद्योगिक क्षेत्र (आईए) से सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस और दो होंडा शाइन, जबकि सैलाना थाना क्षेत्र से दो सुपर स्प्लेंडर चोरी करने की बात भी सामने आई है।

सागर में वन अमले पर हमला, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश

रात के अंधेरे में वन भूमि पर कर रहे थे जुताई, टीम ने रोका तो पथराव किया, डंडों से पीटा

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के शाहगढ़ वन परिक्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण रोकने पहुंची टीम पर रविवार देर रात हमला कर दिया गया। छोटे बंधा के पास कुछ लोग रात के अंधेरे में वन विभाग की जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण रोकने के साथ ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई शुरू की।

इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने वनकर्मियों से विवाद करते हुए डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी और वन पाल नारायण सिंह पलिया घायल हुए हैं। तिवारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ट्रैक्टर जब्त करने के दौरान हुआ विवाद: वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जुताई रोकने और ट्रैक्टर जब्त करने का प्रयास किया। इसी दौरान टीम और मौके पर मौजूद लोगों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद लोगों ने वनकर्मियों पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गए। पत्थर लगने से उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी के सिर में गंभीर चोट आई। वन पाल नारायण सिंह पलिया भी घायल हुए। तिवारी को पहले शाहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

3 आरोपियों पर मामला दर्ज: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वन विभाग की शिकायत पर शाहगढ़ पुलिस ने निवाई निवासी हरिराम यादव, अमित यादव और हरेन्द्र यादव के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का वीडियो सामने आया: घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वन विभाग की टीम ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठकर उसे आगे बढ़ा देता है। इससे वन विभाग की टीम के कर्मचारी बाल-बाल बचते नजर आ रहे हैं।

बरेती खुर्द में मां बारहभुजी का पूजन-पाठ, वेदी निर्माण के साथ हुई कलश स्थापना

मीडिया ऑडीटर, जवा (निप्र)। ग्राम बरेती खुर्द में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी मां बारहभुजी की आराधना का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया धार्मिक अनुष्ठान के तहत आचार्यों एवं विद्वानों द्वारा विधि-विधान से वेदी निर्माण कराया गया इसके बाद गौरी-गणेश पूजन और कलश स्थापना के साथ मां बारहभुजी का पूजन-पाठ संपन्न हुआ आयोजन में धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना की गई आयोजकों का उद्देश्य क्षेत्र में धार्मिक आस्था और परंपराओं को बनाए रखना तथा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को मां बारहभुजी के दर्शन और पूजन से जोड़ना है उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवरात्रि के अवसर पर जवा स्थित उमाहिश्वर गुरु गायत्री मंदिर में भी इसी प्रकार का विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस वर्ष ग्राम बरेती खुर्द में मां बारहभुजी के पूजन-पाठ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है।

दिव्यांगजन सम्मान समारोह में सेवा, समर्पण और सशक्तीकरण का संदेश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, समर्पण और जनकल्याण के संकल्प से प्रेरित होकर महाबली गौतम द्वारा दिव्यांगजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की समारोह का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना रहा आयोजन के दौरान दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और जनकल्याण के संकल्प से प्रेरणा लेते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान और उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करना सभी का दायित्व है।

सम्मान और समान अवसर पर जोर: समारोह में दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया कहा गया कि एक संवेदनशील और समावेशी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और आगे बढ़ने का मंच उपलब्ध कराए दिव्यांगजनों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक सहभागिता जरूरी है आयोजक महाबली गौतम एवं आयोजन मंडल ने कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया आयोजन को सेवा और सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए दिव्यांगजनों के सम्मान को महत्वपूर्ण बताया गया।

कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता हुए शामिल: कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, मनगवां विधायक नरेंद्र प्रजापति, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

मऊगंज में अंतरविद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से, 19 स्कूलों की टीमें लेंगी हिस्सा

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सत्र 2026-27 की जिला स्तरीय अंतरविद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से शुरू होगी प्रतियोगिता में क्षेत्र के 19 विद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी सभी मुकाबले कलेक्टरेट ग्राउंड, मऊगंज में आयोजित किए जाएंगे प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा जिला क्रिकेट संघ के सचिव संजय तिवारी ने बताया कि विद्यालय स्तर पर क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।इसमें विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे प्रतियोगिता में शामिल टीमों को पूल-ए और पूल-बी में विभाजित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे मैच खेले जाएंगे शुरुआती मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल आयोजित किए जाएंगे पूरी प्रतियोगिता में कुल 18 मैच खेले जाने हैं।

रीवा की बदहाल सड़कों के खिलाफ आप का एक माह का जन-जागरूकता अभियान शुरू

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर की बदहाल और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक माह का जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है अभियान के पहले दिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौराहे पर पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से आम नागरिकों का ध्यान सड़क की समस्याओं की ओर आकर्षित किया पार्टी का उद्देश्य खराब सड़कों की स्थिति को जनता और शासन-प्रशासन के सामने लाना तथा जल्द मरम्मत और सुधार कार्य कराने की मांग उठाना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौराहे पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक अभियान चलाया इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और स्लोगन लेकर खड़े रहे और राहगीरों को शहर की जर्जर सड़कों से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया पार्टी के अनुसार अभियान के दौरान आम नागरिकों का सकारात्मक सहयोग मिला लोगों ने सड़क की समस्या को गंभीर बताते हुए इस पहल के प्रति समर्थन जताया।

गड्ढों से आवागमन प्रभावित होने का आरोप: पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रीवा शहर की कई सड़कों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है जगह-जगह गड्ढों और जर्जर सड़क के कारण वाहन चालकों सहित आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खराब सड़कों से रोजाना गुजरने वाले लोगों को असुविधा होती है इसके बावजूद सड़क सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बनी हुई है कार्यकर्ताओं ने मांग की कि संबंधित विभाग और प्रशासन शहर की सड़कों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करें जिन सड़कों पर गड्ढे और अन्य क्षति है, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए। साथ ही, सड़क सुधार कार्यों की नियमित निगरानी की जाए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

एक माह तक अलग-अलग स्थानों पर चलेगा अभियान: आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि सड़क की समस्या को लेकर यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा आगामी एक माह तक शहर के अलग-अलग स्थानों पर जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इस दौरान पोस्टर, स्लोगन और अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से सड़क की बदहाली का मुद्दा उठाया जाएगा पार्टी का प्रयास रहेगा कि नागरिकों की समस्या प्रशासन तक पहुंचे और सड़क सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मुयमंत्री ने सिंगल लिक से 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को जारी किए 213.41 करोड़ रुपये

जिले के 45,528 हितग्राही लाभान्वित, प्रतिमाह 2 करोड़ 79 लाख 16 हजार 800 रुपये की आर्थिक सहायता जारी

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आज नरसिंहपुर जिले से सिंगल क्लिक के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं के 35 लाख से अधिक हितग्राहियों को सितंबर 2026 की पेंशन राशि सिंगल क्लिक से जारी की गई है। अक्टूबर माह में भुगतान की जाने वाली इस पेंशन राशि के अंतर्गत कुल 213.41 करोड़ रुपये का हितलाभ अंतरित किया गया। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समाज के निर्धन, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों, कल्याणियों, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

वेबकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हितग्राही: मुख्यमंत्री द्वारा नरसिंहपुर में आयोजित पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को वेबकास्ट के माध्यम से जोड़ने के निर्देश दिए गए थे, जिससे वे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता कर सकें है। विदिशा जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी ग्राम पंचायतों में उक्त आयोजन का सीधा प्रसारण देखा सुना गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम श्री हरि वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया था। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जिले के 45,528 हितग्राही लाभान्वित, प्रतिमाह 2 करोड़ 79 लाख 16 हजार 800 रुपये की आर्थिक सहायता जारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक ने बताया है कि विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से वित्तीय वर्ष में कुल 45,528 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इन हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिमाह कुल 2 करोड़ 79 लाख 16 हजार 800 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

नौ योजनाओं के माध्यम से मिल रहा लाभ: जिले में सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से नौ प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें मंदबुद्धि/बहुविकलांगजनों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धाश्रम, सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना तथा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पात्र हितग्राहियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

योजनावार हितग्राहियों की स्थिति: जिले में योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या इस प्रकार है- मंदबुद्धि/बहुविकलांगजनों को आर्थिक सहायता: 2,123 हितग्राही।मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना: 23,930 हितग्राही। कन्या अभिभावक पेंशन योजना: 944 हितग्राही।मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना: 45 हितग्राही। सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना: 419 हितग्राही।सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना: 4,308 हितग्राही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धाश्रम: 1 हितग्राही। सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना: 11,788 हितग्राही। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना: 2,970 हितग्राही शामिल हैं।

जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान करने की पहल: राज्य शासन की पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता वृद्धजनों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इससे बड़ी संख्या में हितग्राहियों को एक साथ पेंशन राशि उपलब्ध कराई गई।

150वीं वर्षगांठ टेस्ट में खास जर्सी पहनकर उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम

एमसीजी में इंग्लैंड से होगी भिड़ंत

मेलबर्न,एजेंसी । ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 150वीं वर्षगांठ टेस्ट के दौरान खास सफेद जर्सी पहनेगी। इस विशेष टेस्ट किट में ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक हरे और सुनहरे रंग को शामिल किया जाएगा, ताकि इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाया जा सके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को इस विशेष किट का अनावरण किया, जिसे 11 मार्च से शुरू होने वाले 150वीं वर्षगांठ टेस्ट से ठीक 150 दिन पहले लॉन्च किया गया। इस ऐतिहासिक किट में पारंपरिक गोल्डन वॉटल ट्रिम की जगह सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एक हरा प्लैकेट भी जोड़ा गया है। जर्सी की स्लीव पर सुनहरे रंग में 150वीं वर्षगांठ टेस्ट का विशेष लोगो और किट निर्माता कंपनी एएसआईसीएस का लोगो लगाया गया है। इसके अलावा, कॉलर, शर्ट और पैंट की साइड सीम पर सुनहरी पाइपिंग दी गई है, जबकि बटनों पर भी सुनहरे रंग की फिनिश दिखाई देगी। यह डिजाइन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की विरासत और इस ऐतिहासिक मुकाबले के महत्व को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है।इसके अलावा, यह किट वैसी ही है जैसी ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम 2025-26 के समर सीजन में लॉन्च होने के बाद से टेस्ट मैचों में पहनती आ रही है। इसके कंधों पर मशहूर एबोरिजिनल आर्टिस्ट आंटी फियोना क्लार्क की बनाई आदिवासी कलाकृति बनी है। 'क्रिकेट डॉट कॉम एयू' के अनुसार, 'लैंड एंड सी' नाम की इस कलाकृति में 'वॉकअबाउट विकेट्स' मोटिफ को शामिल किया गया है। यह डिजाइन ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेशी दौरे पर जाने वाली क्रिकेट टीम एबोरिजिनल इलेवन को श्रद्धांजलि देने की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसी टीम ने 1868 में इंग्लैंड का ऐतिहासिक दौरा किया था और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा था। 150वें वर्षगांठ टेस्ट के शुरुआती तीन दिनों के लिए सभी पब्लिक टिकट बिक चुके हैं - यह मैच डे-नाइट होगा और पिंक बॉल से खेला जाएगा। पिंक बॉल से डे-नाइट मैच के तौर पर खेले जाने वाले 150वें वर्षगांठ टेस्ट के शुरुआती तीन दिनों के टिकट बिक चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का शेड्यूल काफी व्यस्त है। पैट कमिंस की टीम को अगस्त में शुरू हुए 12 महीनों के दौरान 21 टेस्ट मैच खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो अभी साउथ अफ्रीका में तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेल रहा है, 150वीं वर्षगांठ टेस्ट के लिए लौटने से पहले भारत में पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के लिए जाने से पहले अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैच खेलेगा।

सानिया मिर्जा एक लेजेंड खिलाड़ी और मेरी आदर्श हैं

● डब्ल्यू35 लागोस का खिताब जीतने के बाद बोलीं माया राजेश्वरन

नई दिल्ली,एजेंसी । भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन रेवती का मानना ??है कि उनका पहला प्रोफेशनल सिंगल्स खिताब सीनियर सर्किट में उनके सफर की बस शुरुआत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी सानिया मिर्जा से आगे निकलने का सवाल ही नहीं उठता, जिन्हें वह अपना आदर्श मानती हैं। 17 साल की माया ने नाइजीरिया में डब्ल्यू35 लागोस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेशनल सर्किट में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यूक्रेन की येलीजावेता कोट्लियार के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता और फिर मेन ड्रॉ में बिना कोई सेट गंवाए सिंगल्स का खिताब भी अपने नाम किया। 17 वर्षीय माया ने फाइनल में स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को 6-4, 6-2 से हराया और डब्ल्यू35 सिंगल्स खिताब

जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनीं। इस जीत के साथ उन्होंने सानिया मिर्जा के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारत की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक सानिया से आगे निकलने के बारे में पूछे जाने पर माया ने तुरंत इस तुलना को खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने अगली पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी विरासत छोड़ी है। मीडिया के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान माया ने 'आईएएनएस' से ??कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आप असल में उनसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वह एक लेजेंड हैं और हमेशा लेजेंड ही रहेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैं कई मायनों में उन्हें अपना आदर्श मानती हूं, क्योंकि जब मैं देश में बड़ी हो रही थी, तब वह मेरी आदर्श थीं। उन्होंने ही इतने वर्षों बाद देश में टेनिस को पहचान दिलाई है। '

इंटरव्यू और पॉडकास्ट के जरिए सानिया के सफर को देखने वालीं माया ने कहा कि उन्होंने इस टेनिस आइकन के साथ ज्यादा बातचीत तो नहीं की है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह उनके अनुभव से सीख पाएंगी। उन्होंने कहा, 'हालांकि, मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की है। काश मैं कर पाती। वैसे, मैं उन्हें बहुत मानती हूं, उनके सभी पॉडकास्ट और इंटरव्यू सुनती हूं। मुझे लगता है कि सानिया हमेशा एक लेजेंड रहेंगी और हमेशा मेरी आदर्श रहेंगी। '

इस टीनएजर के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि वह खेल में आगे बढ़ रही थी। टूर्नामेंट से पहले दुनिया में 1038वें नंबर पर रहने वाली माया ने मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई किया, फिर पहले राउंड में नंबर वन सीड जस्टिना मिकुलस्काइट को हराया और उसके बाद ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भी जीत हासिल की।

उन्होंने अपना शानदार सफर तब पूरा किया जब उन्होंने फाइनल मुकाबले में स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को 6-4, 6-2 से हराकर प्रो सर्किट में अपना पहला खिताब जीता। इस भारतीय खिलाड़ी ने कोट्लियार के साथ मिलकर चीन की मिन लियू और इटली की कार्लोटा मोसिया को 0-6, 6-2, 10-7 से हराकर डबल्स का खिताब भी जीता था।

2-2 से ड्रॉ रहा वैलेंसिया और रेसिंग सैंटेंडर के बीच खेला गया मुकाबला

सैंटेंडर,एजेंसी । वैलेंसिया सीएफ ने ला लीगा के मैचडे 8 में रियल रेसिंग सैंटेंडर के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस मुकाबले में वैलेंसिया के लिए दानी राबा और डेविड ओटोरबी ने गोल किए। वैलेंसिया ने मैच की शानदार शुरुआत की और मुकाबला शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही बढ़त हासिल कर ली। जेवियर एगुइरे की टीम के लिए दानी राबा ने हाल ही में प्रमोट हुई रेसिंग सैंटेंडर के खिलाफ शुरुआती गोल दागा। हालांकि, मेजबान टीम ने 32वें मिनट में वापसी की। इनिगो विसेंट ने शानदार मूव बनाते हुए यासिर जबिरी को गोल करने का मौका दिया, जिसे उन्होंने भुनाकर स्कोर 1-1 कर दिया। हालांकि, वैलेंसिया के युवा सब्स्टीट्यूट डेविड ओटोरबी ने 65वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 2-2 से ड्रॉ दिलाया। एक अन्य मैच में इस्को ने दो गोल किए और रियल बेटिस ने अपने घरेलू मैदान पर ओसासुना को 5-2 से हराया, जिससे वे ला लीगा में तीसरे स्थान पर पहुंच गए और टॉप पर चल रही बार्सिलोना से पांच अंक पीछे हैं। ओसासुना के डिफेंडर उनाई सैंटोस के फाउल करने के बाद इस्को ने दसवें मिनट में पेनल्टी स्पॉट से गोल करके खाता खोला, और 31वें मिनट में कुचो हर्नांडेज की मदद से एज

अब्दे ने बेटिस की बढ़त को दोगुना कर दिया।

हाफ टाइम के तीन मिनट बाद बेटिस 3-0 से आगे हो गई जब एंटे बुदिमिर का क्लीयरेंस का प्रयास डिएगो लोरेंटे से टकराकर नेट में चला गया, लेकिन बुदिमिर और बेटिस के पूर्व फॉरवर्ड राउल गार्सिया के तेज गोल ने ओसासुना को मुकाबले में वापस ला दिया। इस्को ने मैच में अपना दूसरा गोल करके बेटिस की दो गोल की बढ़त को फिर से कायम किया, जिसके बाद डेब्यू करने वाले जोस एंटोनियो मोरांटे ने स्टॉपेज टाइम में स्कोरिंग पूरी की। दूसरी ओर, रियल सोसिदाद ने दूसरे हाफ में डेपोर्टिवो ला कोरुना की जबरदस्त वापसी की कोशिश को नाकाम करते हुए अपने घरेलू मैदान पर 3-2 से जीत हासिल की, जबकि मैच के आखिर में उनके पास दस खिलाड़ी ही बचे थे।

यश-गुरजपनीत और निशांत की तिकड़ी ने पलटी हारी हुई बाजी

● भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए को तीसरे अनौपचारिक वनडे में 49 रनों से हराया

पुडुचेरी,एजेंसी । भारत-ए ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरे अनौपचारिक वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया-ए को 49 रनों से हराया। यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह और निशांत सिंधु की तिकड़ी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत के लिए हारी हुई बाजी को पलटा। भारत-ए से मिले 276 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए की पूरी टीम 46.2 ओवर में 226 रन बनाकर ऑलआउट हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जोश फिलिप्स और लियाम स्कॉट ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। स्कॉट 26 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, फिलिप्स 48 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 56 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। लाचलान शॉ अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, नाथन मैकस्वीनी 58 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। निखिल चौधरी अनलकी रहे और वह 29 रन बनाने के बाद रनआउट होकर पवेलियन लौटे। मिचेल ओवेन 20 रन बनाने के बाद गुरजपनीत सिंह का शिकार बने। विल सदलैंड ने 7 रन बनाए, तो बेन ड्वारशुइस 5 रन ही बना सके। टॉड मर्फी 6 रन बनाकर यश ठाकुर की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को कैच देकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय पर 177 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 226 रनों पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अगले आखिरी 7 विकेट महज 49 रन जोड़कर गंवाए। यश ठाकुर और निशांत सिंधु ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि गुरजपनीत सिंह ने 56 रन देकर 3 विकेट निकाले। इससे पहले, भारत के पूरी टीम 47.3 ओवर में 275 रन बनाकर ऑलआउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत-ए को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारत-ए की शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए 10.4 ओवर में 83 रन की साझेदारी की। प्रभसिमरन ने 34 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसमें छह चौके शामिल रहे। वहीं, प्रियांश अपने अर्धशतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए और 45 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में तीन चौके और दो छक्के शामिल रहे। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके और 57 गेंदों में 33 रन बनाकर मिचेल ओवेन का शिकार बने। पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले रजत पाटीदार भी इस बार प्रभाव नहीं छोड़ सके और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। निशांत सिंधु भी 5 रन ही बना पाए। एक समय भारत-ए का स्कोर 159 रन पर 6 विकेट था और टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसे में सूर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 77 गेंदों पर 85 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विपराज ने 44 गेंदों में 40 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें छह चौके शामिल थे।

आर्थिक संकट से जूझ रहा था परिवार, रिंकू सिंह को मिला पोछा लगाने का काम

नई दिल्ली,एजेंसी । भारत के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए पहचान बनाई। गुजरात टाइटंस के खिलाफ साल 2023 में लगातार पांच छक्के लगाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले रिंकू ने भारतीय टीम के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी उपयोगिता साबित की है। 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह के पिता घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे, जिनके पांच लड़कों में से एक रिंकू को क्रिकेट से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इतना लगाव कि वह स्कूल के समय भी क्रिकेट खेलना ही पसंद करते। पिता नहीं चाहते थे कि रिंकू क्रिकेट में अपना समय बर्बाद करें। इस वजह से कभी-कभी उनकी पिटाई भी हो जाती। हालांकि, भाइयों ने रिंकू का बखूबी साथ दिया। रिंकू के पास गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कुछ लोगों उनकी मदद भी करते। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में रिंकू क्रिकेट से दूर होने लगे। इस बीच उनका भाई रिंकू को काम दिलवाने के सिलसिले में कोचिंग सेंटर लेकर गया, जहां उन्हें पोछा लगाने का काम मिल रहा था, लेकिन रिंकू को लगा कि इस वजह से उनका क्रिकेट छूट सकता है। ऐसे में उन्होंने यह नौकरी न करते हुए फिर से क्रिकेट खेलना शुरू करने का फैसला लिया। रिंकू सिंह की निगाहें अंडर-16 टीम में जगह बनाने पर थीं। वह दो बार पहले ही राउंड में बाहर निकल चुके थे, जिसके बाद मोहम्मद जीशान और मसूद अमीन ने उनकी मदद की, जिनका मार्गदर्शन रिंकू के लिए मददगार साबित हुआ। रिंकू सिंह को साल 2017 में पंजाब किंग्स ने 10 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा, लेकिन उस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। इसके बाद साल 2018 में रिंकू पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख रुपये का दांव खेला। इन पैसों ने परिवार की आर्थिक दिक्कतों को दूर कर दिया। रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए 14 मुकाबलों में 59.25 की औसत के साथ 474 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल गया। इसके बाद रिंकू ने

मगर नहीं मानी हार

दिसंबर 2023 में भारत के लिए पहला वनडे मैच भी खेला। रिंकू ने भारत के लिए 48 टी20 मुकाबलों में 36.94 की औसत के साथ 702 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, 2 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 55 रन टीम के लिए जुटाए। रिंकू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3,757 रन और लिस्ट-ए क्रिकेट में 2,418 रन बना चुके हैं।

इंदौर में अभिषेक का तूफान, वेस्टइंडीज की 14 रन से हार

● भारत 2-1 से आगे

इंदौर,एजेंसी । भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को 14 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान देश ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पारी की अंतिम गेंद पर 223 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम ने 7 के स्कोर पर संजू सैमसन (3) के रूप में पहला विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 108 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 115 के स्कोर तक पहुंचाया। ईशान 18 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। इस बीच अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 69 रन बनाकर आउट हो गए। आलम ये रहा कि टीम ने 135 रन तक 5 विकेट खो दिए। इसके बाद तिलक वर्मा ने नितीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 34 रन और अक्षर पटेल के साथ सातवें विकेट के लिए 25 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। तिलक वर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नितीश रेड्डी ने 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए। मेहमान खेमे से रोस्टन चेज, शमर जोसेफ और शमर स्प्रिंगर ने 2-2 विकेट निकाले। कीमो पॉल और गुडाकेश मोती ने 1-1 विकेट चटकाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज निर्धारित ओवरों में 209/7 का स्कोर ही बना सकी। इस टीम को भी 7 के स्कोर पर पहला झटका लगा। कप्तान शाई होप महज 5 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद शिमरॉन हेटमायर ने कामिल पूरण के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 60 रन जुटाए।

तिलक वर्मा ने पूरा किया खास 'अर्धशतक', कोहली-रोहित के क्लब में हुए शामिल

इंदौर,एजेंसी । टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 14 रनों से हराया। भारत से मिले 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 209 रन ही बना सकी। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में खास अर्धशतक पूरा किया। दरअसल, तिलक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर 50 कैच पूरे कर लिए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के महज पांचवें खिलाड़ी बने हैं। तिलक से पहले यह उपलब्धि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने हासिल की है। इस लिस्ट में 65 कैच लेकर रोहित सबसे ऊपर मौजूद हैं। वहीं, हार्दिक पांड्या ने 64, सूर्यकुमार ने 58 और कोहली ने 54 कैच पकड़े हैं।

तीसरे टी20 में तिलक का प्रदर्शन बल्ले से भी दमदार रहा। उन्होंने महज 16 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 चौके लगाए। दूसरे टी20 में भी तिलक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 44 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तीसरे टी20 में तिलक के अलावा, भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली। अभिषेक ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए। वहीं, ईशान किशन ने 18 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसके दम पर भारत की टीम 223 रनों के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम शिमरोन हेटमायर (43 रन) और कामिल पूरन (42 रन) की दमदार पारियों के बावजूद लक्ष्य से 14 रन दूर रह गई। शेरफेन रदरफोर्ड ने 20 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि शमर स्प्रिंगर ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि, दूसरे टी20 में शतकीय पारी खेलने वाले कप्तान शाई होप तीसरे टी20 में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 44 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि नमन धीर ने 2 विकेट झटके।

रवींद्र जडेजा का चला बल्ला, सौराष्ट्र के लिए लगाया शतक, रिंकू ने भी बिखेरा जलवा

नई दिल्ली,एजेंसी । रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन की शुरुआत रवींद्र जडेजा ने सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए शानदार अंदाज में की है। जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। वहीं, उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंह ने भी शतक लगाया। जडेजा ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलते हुए 209 गेंदों का सामना करते हुए 102 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए। जडेजा जब बल्लेबाजी करने उतरे, तो सौराष्ट्र का स्कोर 3 विकेट खोकर 120 रन था। उन्होंने चौथे विकेट के लिए चिराग जानी के साथ मिलकर 31 रनों की साझेदारी निभाई। चिराग के आउट होने के बाद प्रेरक मांकड़ के रूप में जडेजा को अच्छा जोड़ीदार मिला। दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 205 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई। प्रेरक ने 150 गेंदों का सामना करते हुए 129 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जडेजा और प्रेरक की शतकीय पारी की बदौलत सौराष्ट्र की टीम 392 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। चिराग जानी ने 83 रनों का योगदान दिया। वहीं, बिहार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंह ने भी शतकीय पारी खेली। रिंकू ने 168 गेंदों में 112 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। रिंकू ने माधव कौशिक के साथ मिलकर 312 गेंदों में 207 रनों की साझेदारी निभाई। माधव ने भी 150 रनों की दमदार पारी खेली। बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए दीपक हुड्डा ने गोवा के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 98 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। हालांकि, राजस्थान की ओर से खेलते हुए मानव सुथार बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद सिराज त्रिपुरा के खिलाफ पहली पारी में कोई विकेट नहीं चटका सके। रविवार को कर्नाटक की ओर से खेलते हुए केएल राहुल बल्ले से फ्लॉप रहे थे और वह सिर्फ 4 रन ही बना सके थे ।

खबर संक्षेप

धमतरी में 'निदान-03' शिविर,दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन को सुगम बनाने की ऐतिहासिक पहल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। ,धमतरी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय 'निदान-03' विशेष शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस अभिनव शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सहज व सुविधाजनक बनाना था। जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस आयोजन के अंतिम दिन भी जिलेभर से पहुंचे दिव्यांगजनों और बुजुर्गों ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर शिविर का अभूतपूर्व लाभ उठाया। शिविर स्थल पर सुबह से ही जरूरतमंदों का तांता लगा रहा, जहां विशेषज्ञों की टीम ने दिव्यांगजनों की आवश्यकता का आकलन कर उन्हें कृत्रिम अंग, कैलिपर्स, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र जैसे महत्वपूर्ण सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए।

सेवा संकल्प अभियान-2026 : सेवा की कहानी: पति के निधन के बाद चार बेटियों का भविष्य संवारने का उठाया बीड़ा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। पति के निधन के बाद चार बेटियों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और उनके बेहतर भविष्य की चिंता। आर्थिक कठिनाइयों के बीच एक मां के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने स्वरोजगार की राह चुनी। यह प्रेरक कहानी सरगुजा जिले की मती इंदु लता गुप्ता की है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण की सहायता से डेयरी व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, दूसरी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रही है और दो अन्य बेटियां भी अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखे हुए हैं। इंदु लता की सफलता केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी नहीं, बल्कि एक मां के संघर्ष, साहस और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति समर्पण की मिसाल है। सक्षम योजना से मिला आर्थिक सहयोग उनके लिए आजीविका का साधन बनने के साथ बेटियों की उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण सहारा साबित हुआ है। पति के निधन के बाद बढ़ीं जिम्मेदारियां, बेटियों की पढ़ाई जारी रखना था सबसे बड़ा संकल्प इंदु लता गुप्ता बताती हैं कि पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। चार बेटियों की परवरिश और घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। नियमित आय का कोई साधन नहीं होने के कारण परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन परिस्थितियों में उन्हें सबसे अधिक चिंता बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य की होती थी। वे चाहती थीं कि आर्थिक परेशानियों के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। इसके लिए उन्होंने स्वयं कुछ काम शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि परिवार की आजीविका चलाने के साथ बेटियों की शिक्षा का खर्च भी उठा सकें।

सेवा की कहानी: खाली पड़ी जमीन बनी आजीविका का सहारा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कभी जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा था, आज वही जमीन सरगुजा जिले के पहाड़ी कोरवा किसान फूना राम के लिए आजीविका की नई उम्मीद बन गई है। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाली पड़ी जमीन पर आजीविका डबरी का निर्माण होने से अब वे मछली पालन से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बारिश के पानी से डबरी भरने के बाद उन्होंने उसमें मछली बीज डाला है। मछलियां तैयार होने पर उनकी बिक्री से परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की उम्मीद है। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घंघरी निवासी फूना राम पहाड़ी कोरवा की यह कहानी जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का उदाहरण है। ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से निर्मित डबरी ने उन्हें उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग करने और मछली पालन जैसी आयमूलक गतिविधि से जुड़ने का अवसर दिया है। खाली पड़ी जमीन पर बनी डबरी, वर्षा जल संरक्षण से मिला आजीविका का अवसर फूना राम पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि उनकी जमीन का एक हिस्सा लंबे समय से खाली पड़ा था। इस भूमि का उपयोग किसी आयमूलक गतिविधि के लिए नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण की सुविधा मिलने से उन्होंने अपनी खाली जमीन पर डबरी बनवाई। वर्षा ऋतु के दौरान डबरी में पर्याप्त पानी एकत्रित हुआ। पानी की उपलब्धता को देखते हुए फूना राम ने मछली पालन शुरू करने का निर्णय लिया और डबरी में मछली बीज छोड़ा। इस पहल से एक ओर वर्षा जल का संचय संभव हुआ है, वहीं दूसरी ओर खाली पड़ी जमीन आजीविका गतिविधि का आधार बन गई है। अब फूना राम को उम्मीद है कि मछलियां तैयार होने के बाद उनकी बिक्री से परिवार को अतिरिक्त आमदनी होगी। मछली पालन से बढ़ेंगे आय के साधन, परिवार की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत फूना राम बताते हैं कि डबरी निर्माण से पहले उनकी जमीन का यह हिस्सा खाली पड़ा रहता था। अब उसी स्थान पर पानी का संचय हो रहा है और मछली पालन की गतिविधि शुरू हो गई है। उन्होंने डबरी में मछली बीज डाल दिया है। मछलियों के विकसित होने के बाद उन्हें बेचकर आय अर्जित करने की योजना है। इससे परिवार को आजीविका का एक अतिरिक्त साधन मिलेगा।

पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सड़कों, पुलों और भवनों का किया निरीक्षण

- अधिकारियों और ठेकेदारों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
- निर्माण कार्यों की होगी कड़ी मॉनिटरिंग, फील्ड पर प्रगति जांचने होंगे औचक निरीक्षण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। बरसात के बाद सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण को रफ्तार देने की पूरी तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता और समय-सीमा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काम की प्रगति अब केवल दफ्तरों की रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी खुद मैदान में उतरकर निर्माण की वास्तविक स्थिति परखेंगे। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ औचक निरीक्षण से भी गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखी जाएगी। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने गरियाबंद जिले का दौरा कर सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। सचिव बंसल ने गरियाबंद जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर निर्माणाधीन परियोजनाओं की जमीनी स्थिति देखी। उन्होंने फिंगेश्वर विकासखंड में कोपरा-पोखरा मार्ग के 26.20 किलोमीटर लंबे मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस परियोजना में पुल-पुलियों के निर्माण कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने राजिम में नवीन मेला स्थल चौबेबांधा से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण की प्रगति भी देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और निर्माण में गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सड़क परियोजनाओं के साथ सचिव बंसल ने गरियाबंद में निर्माणाधीन शासकीय भवनों का भी जायजा लिया। उन्होंने व्यवहार न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे दो डी-टाइप आवासगृहों, जिला परिवहन कार्यालय भवन तथा 40 जीएडी आवासगृहों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिव बंसल गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में भी पहुंचे। उन्होंने कसाबाय-पतोरा दादर मार्ग के आरडी 135 में चचंगी नाला पर निर्मित पुल एवं पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कसाबाय-सातधार मार्ग में हलफली नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित इन परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। मैदानी निरीक्षण के बाद सचिव बंसल ने गरियाबंद सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए काम में आ रही समस्याओं और बाधाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों को गति देने के साथ गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। बरसात के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाने विभागीय अमले को सक्रियता से काम करना होगा। कार्यों की सतत निगरानी और वरिष्ठ अधिकारियों के मैदानी निरीक्षण से निर्माण की वास्तविक प्रगति पर नजर रखी जाएगी। सचिव बंसल ने लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय और कार्यालय परिसर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में स्वच्छता और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने तथा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता व्ही. के. भतपहरी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंतागण उपस्थित थे।

सेवा संकल्प अभियान : महेश नाग का कच्चे शेड से शुरू हुआ सफर अब पक्के मकान और सफल डेयरी व्यवसाय तक पहुंचा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उलनार निवासी महेश नाग की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि सरकारी योजनाओं का सही मार्गदर्शन मिले और व्यक्ति में कड़ी मेहनत का जज्बा हो, तो जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। पूर्व में केवल खेती और मजदूरी पर आश्रित रहने वाले महेश के पास आजीविका के साधन के रूप में कुछ दुधारू मवेशी जरूर थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पशुओं के सुरक्षित आवास की थी। पक्का शेड न होने के कारण मवेशियों को कच्चे और जर्जर शेड में रखना पड़ता था, जहां अत्यधिक ठंड, तेज धूप और मूसलाधार बारिश के चलते वे लगातार बीमार पड़ जाते थे। पशुओं के अस्वस्थ रहने से दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ गई थी, जिसके कारण महेश को पशुपालन से कोई ठोस आर्थिक संबल नहीं मिल पा रहा था।

परिवार की इस गंभीर समस्या और संघर्ष को देखते हुए ग्राम पंचायत उलनार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उनकी निजी जमीन पर दुधारू पशु शेड निर्माण की स्वीकृति दी गई। कुल एक लाख 49 हजार रुपये की स्वीकृत लागत से पंचायत के तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हवादार, पक्के फर्श और सर्वसुविधायुक्त शेड का निर्माण 16 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक पूरा कराया गया। अनुकूल और सुरक्षित वातावरण मिलते ही मवेशियों की सेहत सुधरने लगी, जिससे दूध उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा दर्ज हुआ।

उत्पादन में हुई इस बढ़ोतरी ने महेश के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी और उन्होंने इसे एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में तब्दील कर दिया। अब वे प्रतिदिन सुबह और शाम जगदलपुर के आसपास के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुद घर-घर जाकर शुद्ध व ताजा दूध का वितरण करते हैं। उनकी इस निष्ठा, समयबद्धता और गुणवत्ता के कारण ग्राहकों के बीच उनकी एक विश्वसनीय पहचान बन चुकी है।

नोनी सुरक्षा योजना से आंचल के सपनों को मिला संबल, एक लाख रुपये का बॉन्ड बना उज्ज्वल भविष्य का आधार

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। हर मां का सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को लेकर चिंता बनी रहती है। छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों को बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णापुर निवासी मती मानती राजवाड़े की बेटी आंचल राजवाड़े को भी इस योजना का लाभ मिला है। आंचल के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है, जिससे परिवार को बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत आंचल की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नोनी सुरक्षा योजना से मिलने वाला लाभ परिवारों को बेटियों की उच्च शिक्षा और आगे की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में उपयोगी साबित हो रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से रोशन हुआ राजपूत परिवार का जीवन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक खुशहाली का नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही अतिरिक्त आर्थिक सहायता से यह योजना आम नागरिकों के लिए और अधिक लाभकारी बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी के सहयोग से अब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना आसान और किफायती हो गया है। योजना के माध्यम से प्रदेश के अनेक परिवार न केवल बिजली बिल के खर्च से राहत प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। इस योजना की सफलता की प्रेरक मिसाल बेमेतरा शहर निवासी बीरेन्द्र राजपूत का परिवार है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मती द्रौपती राजपूत के नाम पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराया। योजना के अंतर्गत उन्हें 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई, जो आवेदन के मात्र 15 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई। इस आर्थिक सहायता से सोलर पैनल स्थापित करने का वित्तीय बोझ कम हुआ और उनका परिवार बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सका। बीरेन्द्र राजपूत बताते हैं कि सोलर पैनल लगवाने के बाद उनके घर के बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली के कारण मासिक बिल शून्य या बेहद कम आ रहा है। इससे परिवार के घरेलू बजट में राहत मिली है ।

सेवा संकल्प अभियान: 'निदान-03' शिविर से संवर रही दिव्यांगजनों की जिंदगी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत धमतरी जिले में आयोजित तीन दिवसीय 'निदान-03' विशेष शिविर दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी दैनिक गतिविधियों को सुगम करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। नगरी और धमतरी में आयोजित इन शिविरों के शुरुआती दो दिनों में कुल 632 दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया, जिन्हें एक ही छत के नीचे कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और शासकीय योजनाओं का पूरा संबल प्रदान किया गया। एक ही छत के नीचे मिलीं तमाम शासकीय सुविधाएं शिविर के पहले दिन 8 अक्टूबर को नगरी विकासखंड के श्रृंगी ऋषि हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शिविर में 172 दिव्यांगजन शामिल हुए। यहाँ पात्र हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक और वॉकर वितरित किए गए। साथ ही, नौ दिव्यांगजनों के कृत्रिम हाथ-पैर तैयार करने के लिए आवश्यक माप और प्रक्रिया पूरी की गई, जबकि 18 दिव्यांगता प्रमाण पत्र और 44 यूडीआईडी कार्ड भी प्रदान किए गए। श्रृखला के दूसरे दिन 10 अक्टूबर को धमतरी के इंडोर स्टेडियम में भव्य शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ 460 दिव्यांगजन पहुँचे और इनमें से 359 हितग्राहियों को विभिन्न उपकरणों व सुविधाओं से लाभान्वित किया गया।

सेवा की कहानी : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से मिला स्वरोजगार का संबल, बेहतर हुई जिंदगी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छोटे कारोबार से परिवार की जरूरतें पूरी करने और बच्चों को बेहतर भविष्य देने की चाह रखने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने पाली नगर पंचायत के महादेव पटेल जैसे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग देकर स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। योजना के तहत मिले ऋण से महादेव पटेल ने अपने काम का विस्तार किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। लाभार्थी महादेव पटेल पहले सीमित स्तर पर सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आमदनी सीमित होने के कारण घरेलू जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें पहली बार 15 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहायता का उपयोग उन्होंने अपनी पत्नी मती सुलेखा पटेल के साथ ठेले पर फल की दुकान शुरू करने में किया। नियमित मेहनत और व्यवसाय से होने वाली आमदनी ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से संबल दिया। कारोबार से आय बढ़ने के साथ घर की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हुआ और बच्चों की शिक्षा के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध होने लगे।

सेवा संकल्प से संवरती ज़िंदगी : अब नारायणपुर के दूरस्थ अबुझमाड़ (कुतुल) के नयापारा में भी पहुंचेगा शुद्ध पेयजल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत राज्य के अंतिम छोर पर बसे वनांचल और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार अब ज़मीनी हक़ीकत बनता जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र ग्राम परपा (कुतुल) के नयापारा में नलकूप खनन का कार्य तेज़ी से प्रारंभ कर दिया गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित आवागमन के बावजूद शुरू की गई इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों को जल्द ही घर के समीप शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में विकास की एक नई किरण जगी है। वनांचल के दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाना केवल एक बुनियादी सुविधा का विस्तार नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सीधे तौर पर बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुतुल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ भौगोलिक विसंगतियाँ और आवागमन की दुश्वारियाँ विकास कार्यों के क्रियान्वयन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती हैं, वहाँ प्रशासन की यह पहल स्थानीय लोगों के जीवन को सुगम बनाने का सशक्त माध्यम बन रही है। पारंपरिक स्रोतों से पानी ढोने की मजबूरी झेल रहे परिवारों के लिए यह नलकूप खनन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण पहल के धरातल पर उतरने से ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए पानी जुटाने की लंबी और श्रमसाध्य मशक्कत से राहत मिलेगी। घर के नज़दीक ही स्वच्छ जल उपलब्ध होने से न केवल उनका बहुमूल्य समय बचेगा, बल्कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग अन्य रचनात्मक व आजीविका संबंधी कार्यों में कर सकेंगे। इसके साथ ही, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों के खतरे को कम करने तथा ग्रामीण आंचल में बेहतर स्वास्थ्य संबंधी आदतों को बढ़ावा देने में भी बड़ी मदद मिलेगी। नारायणपुर जिले के इन दूरस्थ अंचलों में जल स्रोतों का विकास और उनका सुचारू रखरखाव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राज्य शासन हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

महिलाओं के हुनर से रोशन होंगे दीप, फूलबाती बनाकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहीं बेमेतरा की महिलाएं

लखपति दीदी पहल से झलक, झंकार और गायत्री सेवा महिला स्वसहायता समूहों को मिला स्वरोजगार का अवसर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही घर-आंगन को दीपों से रोशन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच बेमेतरा जिले की महिला स्वसहायता समूहों की सदस्य अपने हुनर और मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। उनके हाथों से तैयार हो रही फूलबाती न केवल दीपावली के दीयों को रोशन करेगी, बल्कि महिलाओं के जीवन में आर्थिक खुशहाली और आत्मविश्वास का नया उजाला भी बिखेरेगी। लखपति दीदी पहल के अंतर्गत जिले के झलक, झंकार और गायत्री सेवा महिला स्वसहायता समूहों की महिलाएं फूलबाती निर्माण को आजीविका का साधन बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से महिला स्वसहायता समूहों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ घर पर ही आय अर्जित करने के अवसर प्राप्त कर रही हैं। समूह की महिलाओं को मशीन के माध्यम से रुई की फूलबाती बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मशीन के संचालन, रुई से फूलबाती तैयार करने की तकनीक, कच्चे माल के उपयोग तथा तैयार उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही समूह को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई, जिससे महिलाओं को मशीन एवं आवश्यक कच्चा माल खरीदने में मदद मिली। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समूह की महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ फूलबाती निर्माण का कार्य शुरू किया। शुरुआत में महिलाओं के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन निरंतर अभ्यास और सामूहिक प्रयासों से वे इस कार्य में दक्ष होती गईं। महिला स्वसहायता समूहों की इस पहल की विशेषता यह है कि महिलाओं को आजीविका अर्जित करने के लिए अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाना पड़ता। वे सुबह घरेलू कामकाज निपटाने के बाद उपलब्ध समय में समूह के साथ मिलकर फूलबाती निर्माण करती हैं। मशीन की सहायता से फूलबाती तैयार करने का कार्य अपेक्षाकृत सरल होने के कारण महिलाएं कम समय में अधिक उत्पादन कर सकती हैं। इससे उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। समूह की महिलाओं के लिए यह कार्य केवल अतिरिक्त कमाई का साधन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान का आधार भी बन रहा है। पहले जिन महिलाओं की दिनचर्या मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित थी, वे अब उत्पादन, पैकेजिंग, बिक्री और बाजार से जुड़ी गतिविधियों में भी भागीदारी निभा रही हैं। सामूहिक रूप से कार्य करने से उनमें नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और आर्थिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। दीपावली के अवसर पर घरों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के लिए फूलबाती की मांग बढ़ जाती है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए समूह की महिलाएं पूरी लगन और उत्साह के साथ फूलबाती निर्माण में जुटी हुई हैं। त्योहारी सीजन में स्थानीय बाजारों से मिलने वाले ऑर्डर ने महिलाओं के उत्साह को और बढ़ाया है। समूह की सदस्य तैयार फूलबाती की पैकिंग कर उन्हें बाजार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पादों की बिक्री और विपणन से समूह की आय बढ़ाने के नए अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं की इस पहल को जिला प्रशासन का भी सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है। अधिकारियों द्वारा समूह की महिलाओं के तैयार उत्पादों की खरीदी किए जाने से उन्हें अपने कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता ने महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। समूह की महिलाएं अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार में पहचान बनाने का भी प्रयास कर रही हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा